इन आरईः बरूबरी संघ और

बस्तियों का स्थानांतरण

अनुच्छेद 143 (1) के तहत संदर्भ

भारत का संविधान

(बी. पी. सिन्हा, सी. जे., एस. के. दास, पी. बी. गजेन्द्र

गडकर, ए. के. सारकर, के. सुब्बा राव,

एम. हृदयतुल्ला, के. सी. दास

गुप्ता और जे. सी. शाह, जे. जे.)

राष्ट्रपति का

संदर्भ-भारत-पाकिस्तान समझौता, 1958-बरुबारी संघ का विभाजन और कूच-बिहार परिक्षेत्रों का आदान-प्रदान-यदि

इसमें क्षेत्र का हस्तांतरण-कार्यान्वयन-भारत के संविधान, कला का संशोधन शामिल है। 1 , 3 , 368 .

12 अगस्त, 1947 के रेडक्लिफ पुरस्कार के परिणामस्वरूप,

बेरूबरी संघ संख्या 12 पश्चिम बंगाल के भीतर आता था और 26 जनवरी, 1950 को लागू हुए संविधान द्वारा ऐसा माना जाता था और तब से उस आधार पर शासित है। रेड क्लिफ पुरस्कार के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ विवाद उत्पन्न हुए लेकिन उन विवादों को तय करने के लिए पक्षों के बीच समझौते द्वारा गठित बैग आयोग के समक्ष बेरूबरी मुद्दे में नहीं था। उस आयोग ने 26 जनवरी, 1950 को अपना पुरस्कार दिया। पाकिस्तान ने पहली बार 1952 में बेरूबरी का सवाल उठाया और आरोप लगाया कि

रैडक्लिफ पुरस्कार के तहत इसे पूर्वी बंगाल का हिस्सा बनाया जाना चाहिए और गलत तरीके से पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया। 28 अगस्त, 1949 को कूच राज्य के शासक-बिहार 3 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

251 .

कूच-बिहार का अंततः 1 जनवरी, 1950 को पश्चिम बंगाल में विलय कर दिया गया, ताकि इसका एक हिस्सा बन सके। यह पाया गया कि कुछ क्षेत्र जो कूच-बिहार राज्य से संबंधित थे, विभाजन के बाद पाकिस्तान में परिक्षेत्र बन गए, और इसी तरह कुछ क्षेत्र

पाकिस्तान के अंतःक्षेत्र भारत में गिर गए।

जिससे उत्पन्न तनाव और संघर्ष को दूर करने के लिए

भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों ने 10 सितंबर, 1958 को एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसे भारत-पाकिस्तान समझौता कहा जाता है।

और उस समझौते की मद 3 और 10 में भारत और पाकिस्तान के बीच बेरूबरी संघ के आधे-आधे विभाजन का प्रावधान किया गया था और

पाकिस्तान में कूच-बिहार एन्क्लेव और भारत में पाकिस्तानी टैन एन्क्लेव के आदान-प्रदान के लिए।

बाद में दोषियों के बारे में संदेह पैदा हो गया

उक्त मदों का उल्लेख करते हुए, भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में मामला। 143 (1) कॉन्स्टिट्यूशन की

ट्यूशनः

माना जाता है कि समझौते की मद संख्या 3 कोई तरीका नहीं छोड़ती है

इस बात पर संदेह है कि इसके पक्षकार इस प्रकार इस विवाद को निपटाने की कोशिश कर रहे थे

पुरस्कार के अलावा, सौहार्दपूर्ण तरीके से, और तदर्थ आधार पर

क्षेत्र को आधा और आधा विभाजित करें। वहाँ बिल्कुल कोई भारतीय नहीं है

इसमें यह उल्लेख किया गया है कि वे पुरस्कार की व्याख्या करना चाहते थे और

उस आधार पर सीमा निर्धारित करें। संबंधित प्रश्न

इसलिए बेरूबरी पर इस आधार पर विचार किया जाना चाहिए कि

से संबंधित समझौते पर अधिक बल के साथ लागू होता है परिक्षेत्रों का आदान-प्रदान।

इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि कार्यान्वयन

समझौता पश्चिम बंगाल की सीमा को बदल देगा और प्रभावित करेगा संविधान की पहली अनुसूची में प्रविष्टि 13 के रूप में

वास्तव में बेरूबरी को पश्चिम बंगाल का हिस्सा माना जाता था और

पुरस्कार की तारीख से इस तरह से शासित था और इस प्रकार कॉम था

संविधान के प्रारंभ से पहले उसमें रखा गया था।

इसके विपरीत कोई भी तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

ऑस्ट्रेलिया राज्य बनाम। विक्टोरिया राज्य, (1911) 12

सी. एल. आर. 667 और द स्टेट ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया बनाम विक्टोरिया राज्य,

[1914] ए. सी. 283 , विशिष्ट और अप्रयोज्य रखा गया।

यद्यपि प्रस्तावना को एक कुंजी के रूप में वर्णित करना सही हो सकता है।

सरकार को स्पष्ट रूप से या निहितार्थ द्वारा प्रदान करना। यह निषेधों और सीमाओं के बारे में भी उतना ही सच है। इसलिए यह कहना सही नहीं था कि प्रस्तावना किसी भी तरह से इसे सीमित कर सकती है। राष्ट्रीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों को सौंपने की संसद की शक्ति। न ही यह कहना सही था कि कला। 1 (3) ((ग) उन्होंने ऐसा किया।

अनुच्छेद 1 (3) (सी) का सही अर्थ लगाया गया है, जो प्राप्त करने की कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है।

विदेशी क्षेत्र लेकिन केवल ऐसे क्षेत्रों के स्वचालित अवशोषण को मान्यता देता है जो भारत द्वारा अपने संप्रभु अधिकार में अधिग्रहित किए जा सकते हैं और परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय क्षेत्र को सौंपने की शक्ति को निहितार्थ से बाहर नहीं करता है। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय, रिपोर्ट में संशोधन करने की शक्ति

[1960]

अनुच्छेद के तहत संविधान। 368 संसद को शक्ति दें

कला में संशोधन करना। 1 (3) (ग) ताकि राष्ट्रीय क्षेत्र को सौंपने की शक्ति भी शामिल की जा सके। इसलिए यह कहना गलत था कि

भारत के संप्रभु राज्य में संप्रभुता के दो आवश्यक गुणों का अभाव था, अर्थात्, विदेशी क्षेत्र प्राप्त करने की शक्ति और राष्ट्रीय क्षेत्र को सौंपने की शक्ति, और यह कि कानून की कोई भी प्रक्रिया विचाराधीन समझौते को मान्य नहीं कर सकती थी।

यद्यपि क्षेत्र का ऐसा समर्पण, जो कानून में

संप्रभुता के हस्तांतरण से मानवीय दृष्टिकोण से बहुत कठिनाई होनी चाहिए, अपनी संधि बनाने की शक्ति के प्रयोग में ऐसा करने का एक संप्रभु राज्य का अधिकार और ऐसी सीमाओं के अधीन जो संविधान, स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा लागू कर सकता है, कभी भी संदेह में नहीं हो सकता है और यह सवाल कि क्या संधि को सामान्य कानून द्वारा या संवैधानिक संशोधन द्वारा लागू किया जा सकता है, प्रावधानों पर निर्भर होना चाहिए। स्वयं संविधान से।

यह कला के निर्माण में माना जा सकता है। 3 कि कॉन्स्टिट्यूशन

संविधान ने घटक राज्यों की क्षेत्रीय सीमाओं में परिवर्तन पर विचार किया और उनकी क्षेत्रीय अखंडता की कोई गारंटी नहीं थी। मोटे तौर पर, वह लेख टेरी से संबंधित है

न कि केवल भाषाई या अन्य आधार पर उनका पुनर्गठन, बल्कि भारत के संविधान राज्यों के बीच क्षेत्रीय समायोजन। अनुच्छेद 3 (सी) किसी राज्य के क्षेत्र को कम करने से संबंधित है और यह सुझाव देना अनुचित है कि यह राज्य को कवर करने के लिए पर्याप्त चौड़ा है। राष्ट्रीय क्षेत्र का समर्पण। वास्तविक स्थिति यह है कि संविधान में स्पष्ट रूप से विदेशी क्षेत्र के अधिग्रहण या राष्ट्रीय क्षेत्र के हस्तांतरण का प्रावधान नहीं है; प्रत्येक संप्रभु राज्य में इस संबंध में शक्तियां निहित हैं।

नतीजतन, समझौते को लागू नहीं किया जा सकता है

कला से संबंधित कानून। 3 और कला से संबंधित कानून। 368 अपरिहार्य होगा।

अतः यह माना जाता है कि संसद अनुच्छेद के तहत कार्य करती है।

368 बेरूबारी और एन्क्लेव दोनों को शामिल करते हुए विचाराधीन समझौते को प्रभावी बनाने और लागू करने के लिए कानून बना सकते हैं या कला में संशोधन करने वाला कानून पारित कर सकते हैं। 3 ताकि भारत के क्षेत्र के हस्तांतरण के मामलों को शामिल किया जा सके और उसके बाद संशोधित कला के तहत एक कानून बनाया जा सके। 3 समझौते को लागू करना।

सलाहकार न्यायनिर्णयः विशेष संदर्भ संख्या 1

1959 का।

आरती के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा संदर्भ

बेरूबरी संघ और परिक्षेत्रों के आदान-प्रदान से संबंधित भारत-पाकिस्तान समझौते के प्रभाव पर भारत के संविधान की धारा 143 (1)।

जिन परिस्थितियों के कारण यह संदर्भ दिया गया

राष्ट्रपति और निर्दिष्ट प्रश्न 1 अप्रैल, 1959 के संदर्भ के पूर्ण पाठ से दिखाई देते हैं, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

जहाँ सीमा आयोग नियुक्त किया गया था

3 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्टों में सर सिरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में

253

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अनुसार, एक पुरस्कार बनाया गया, जिसे इसके बाद "रैडक्लिफ पुरस्कार" के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसकी एक प्रति यहां अनुलग्नक I के रूप में संलग्न की गई है, जो उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (बी) द्वारा गठित पूर्वी बंगाल प्रांत और पश्चिम बंगाल प्रांत की सीमाओं का खनन रोकती है।

और जहाँ कुछ सीमा विवाद हैं

रैडक्लिफ पुरस्कार, डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान की व्याख्या से उत्पन्न हुआ समझौता द्वारा, उक्त उछाल के निर्णय और अंतिम निपटारे के लिए माननीय लॉर्ड जस्टिस अल्गोट बागे के अध्यक्ष के तहत एक न्यायाधिकरण की स्थापना की गई।

भयंकर विवाद और सीमा का सीमांकन

तदनुसार;

और जहाँ उक्त न्यायाधिकरण ने निर्णय दिए

उक्त सीमा विवाद, इस तरह के निर्णयों को इसके बाद "बैग पुरस्कार" के रूप में संदर्भित किया जा रहा है, एक प्रति

जिसे यहाँ अनुलग्नक II के रूप में संलग्न किया गया है;

और जहाँ तक, जलपाई जिले के संबंध में

गुरी, पश्चिम बंगाल प्रांत और पश्चिम बंगाल प्रांत के बीच सीमा रेखा का सीमांकन

रेडक्लिफ पुरस्कार के अनुलग्नक ए बनाने वाली अनुसूची के पैराग्राफ 1 में पूर्वी बंगाल का वर्णन इस प्रकार किया गया है -

निम्नलिखित हैः ---

" सीमा के साथ एक रेखा खींची जाएगी।

जिले में फानसीडेव ए के थाना के बीच

बिहार प्रांत से मिलता है और फिर साथ में तेतुलिया के थानों और राज के बीच की सीमा

गंज; पचागर और राजगंज के थानों, और

पचागर और जलपाईगुड़ी के थानों, और फिर

थाना के उत्तरी कोने के साथ जारी रखें कूच राज्य की सीमा तक देबीगंज

बिहार। दार्जिलिंग का जिला और बहुत कुछ जलपाईगुड़ी जिला इस रेखा के उत्तर में स्थित है।

पटग्राम और जलपाईगुड़ी दिस का कोई अन्य हिस्सा जिला जो पूर्व या दक्षिण में स्थित है, से संबंधित होगा

पूर्वी बंगाल ";

254 और जब भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच एक और विवाद उत्पन्न हुआ कि क्या जलपाईगुड़ी जिले के संबंध में सीमा रेखा के उपरोक्त विवरण को ध्यान में रखते हुए, रैडक्लिफ पुरस्कार ने उक्त जिले में बेरूबरी संघ संख्या 12 के रूप में जाना जाने वाला क्षेत्र पश्चिम बंगाल प्रांत को सौंपा, जैसा कि भारत सरकार द्वारा तर्क दिया गया है या उसने उक्त क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा पूर्वी बंगाल प्रांत को सौंपा है, जैसा कि सरकार द्वारा तर्क दिया गया है।

पाकिस्तान के क्षेत्र (उक्त क्षेत्र के नक्शे में नीले रंग में दिखाए गए) अन्य सीमा समस्याओं के साथ उलझे हुए थे। भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार का ध्यान आकर्षित करना; और जहाँ तक, तनाव के कारणों को दूर करने और सीमा विवादों और समस्याओं को हल करने की दृष्टि से

भारत-पाकिस्तान सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में और उन क्षेत्रों में शांतिपूर्ण स्थिति स्थापित करने के लिए, भारत के प्रधानमंत्री ने भारत सरकार के लिए और उसकी ओर से और पाकिस्तान सरकार की ओर से, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के राष्ट्रमंडल सचिव और पाकिस्तान सरकार के विदेश सचिव द्वारा संयुक्त रूप से दर्ज किए गए नोट में निर्धारित तरीके से उक्त विवादों और समस्याओं में से कुछ का निपटारा करने के लिए एक समझौता किया, जिसकी एक प्रति अनुलग्नक V के रूप में संलग्न की गई है, जैसा कि उक्त 3 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट में सन्निहित है।

255

नोट को इसके बाद "भारत-पाकिस्तान टैन समझौता" के रूप में संदर्भित किया जा रहा है;

और जब भारत-पाकिस्तान समझौता तय होता है

बरूबरी संघ सं. 12 के रूप में ज्ञात क्षेत्र से संबंधित उपरोक्त विवाद, उसके पैराग्राफ 2 में मद (3) में निर्दिष्ट तरीके से, ऐसे समझौते से संबंधित समझौते को इसके बाद "बरूबरी संघ से संबंधित समझौते" के रूप में संदर्भित किया जा रहा है;

और जब भारत-पाकिस्तान समझौता तय होता है

पाकिस्तान में भारतीय परिक्षेत्रों और भारत में पाकिस्तान परिक्षेत्रों के अस्तित्व से उत्पन्न होने वाली उपरोक्त समस्या, निर्धारित तरीके से परिक्षेत्रों के आदान-प्रदान द्वारा परिच्छेद 2 में मद (3) के साथ पठित मद (10) में परिक्षेत्रों के ऐसे आदान-प्रदान से संबंधित समझौता

इसके बाद "एन्क्लेव के आदान-प्रदान से संबंधित समझौते" के रूप में संदर्भित किया जा रहा है;

और जहाँ एक संदेह उत्पन्न हुआ है कि क्या

बरुबारी संघ से संबंधित समझौते के कार्यान्वयन के लिए संविधान के अनुच्छेद 3 से संबंधित संसद के उपयुक्त कानून के माध्यम से या संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के अनुसार संविधान के उपयुक्त संशोधन के माध्यम से या दोनों के माध्यम से किसी भी विधायी कार्रवाई की आवश्यकता होती है।

और जहाँ एक संदेह उत्पन्न हुआ है कि क्या एक उपयुक्त

संविधान के अनुच्छेद 3 से संबंधित संसद का कानून एन्क्लेव के आदान-प्रदान से संबंधित समझौते को लागू करने के लिए पर्याप्त है या क्या, इसके अलावा या वैकल्पिक रूप से,

के प्रावधानों के अनुसार संविधान

संविधान का अनुच्छेद 368 आवश्यक है

उद्देश्य;

और जहाँ संविधान की संभावना है

बरुबारी संघ से संबंधित समझौते के कार्यान्वयन के लिए की गई किसी भी कार्रवाई की राष्ट्रीय वैधता और एन्क्लेव के आदान-प्रदान से संबंधित समझौते पर अदालतों में सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसमें परिहार्य और लंबी मुकदमेबाजी शामिल है;

और जहाँ, यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसे देखते हुए

इससे पहले कहा गया था, मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद कानून के प्रश्न उत्पन्न हुए हैं और वे इस तरह के और इतने महत्वपूर्ण हैं कि यह समीचीन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की राय उस पर प्राप्त की जानी चाहिए; सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1960]

256

अब, इसलिए, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

संविधान के अनुच्छेद 143 के खंड (1) द्वारा मुझ पर

राष्ट्र, मैं, राजेंद्र प्रसाद, भारत के राष्ट्रपति, इसके द्वारा

निम्नलिखित प्रश्नों को उच्चतम न्यायालय को भेजें भारत विचार और उस पर रिपोर्ट के लिए, अर्थात्ः

" (1) क्या इसके लिए कोई विधायी कार्रवाई आवश्यक है

संबंधित समझौते का कार्यान्वयन बरुबारी संघ के लिए?

(2) यदि ऐसा है, तो क्या संसद का एक कानून संबंधित है

संविधान का अनुच्छेद 3 इसके लिए पर्याप्त है

संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान आवश्यक, इसके अतिरिक्त या

वैकल्पिक?

(3) क्या संसद का कानून अनुच्छेद 3 से संबंधित है?

संविधान के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त

आदान-प्रदान से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर

एन्क्लेव्स का या एक संशोधन है

अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान

इस उद्देश्य के लिए आवश्यक संविधान का,

इसके अलावा या विकल्प में?

[अनुलग्नक हटा दिए गए]

1959. 8, 9, 10 और 11 दिसंबर। एम. सी. सीतलवाड़,

भारत के महान्यायवादी, सी. के. दफतरी, भारत के महान्यायवादी, एच. एन. सान्याल, भारत के अतिरिक्त महान्यायवादी, जी. एन. जोशी, आर. एच. ढेबर और टी. एम. सेन, भारत संघ की ओर से। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राज्यों के क्षेत्र की अखंडता की गारंटी भारत के संविधान द्वारा नहीं दी गई है और क्षेत्र से संबंधित प्रश्नों के संबंध में भी संसद को सर्वोच्च बनाया गया है। संविधान का भाग I संघ के भूभाग के संबंध में एक स्व-निहित संहिता है। अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के संविधान में प्रावधान पूरी तरह से हैं

अलग-अलग।

इस संबंध में प्रधानमंत्रियों का समझौता

बरुबारी संघ संख्या 12 में क्षेत्र का कोई हस्तांतरण शामिल नहीं है, लेकिन यह केवल पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल के बीच की सीमा का पता लगाता है, जिसे रैडक्लिफ पुरस्कार द्वारा अस्पष्ट छोड़ दिया गया था। इस प्रकार, समझौते के इस हिस्से को कार्यकारी 3 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट द्वारा लागू किया जा सकता है।

257

कार्रवाई। जहाँ केवल सीमा का निपटान होता है

जैसे, यह भूमि के हस्तांतरण का मामला नहीं है।

दक्षिण ऑस्ट्रेलिया राज्य बनाम। विक्टोरिया राज्य, 12

सी. एल. आर. 667 पेन वी. बाल्टीमोर, 1 वेस। सेन. 444; ग्रैन डेल ऑन ट्रीटीज, आई एडन। , पीपी। 115 और 161; द लेसी ऑफ लैटिमर एट अल वी। पोटेत, 10 एल. एड. 328. क्षेत्र

बेरुबारी संघ संख्या 12 के संघों को नियंत्रित किया जा रहा था

पश्चिम बंगाल असंवैधानिक रूप से और संविधान की पहली अनुसूची के मद 3 के अंतर्गत नहीं आता था। बरुबारी संघ को पश्चिम बंगाल द्वारा अपने स्वयं के क्षेत्र के रूप में प्रशासित किया गया था, हालांकि कानूनी रूप से यह उसके क्षेत्र का हिस्सा नहीं था और इसे श् के मद 3 के अर्थ के भीतर "जैसे कि यह पश्चिम बंगाल का हिस्सा बना" प्रशासित नहीं किया गया था। I. प्रधानमंत्रियों के समझौते के तहत पूर्वी बंगाल को बेरूबरी संघ का एक हिस्सा देने में संविधान की पहली अनुसूची में कोई संशोधन शामिल नहीं था। ए. आई. आर. 1959 कैल. 506 517 और 518 पर।

संघ की कार्यकारी शक्ति सह-व्यापक है।

संसद की शक्तियों के साथ इस सीमा के साथ कि कार्यपालिका संविधान के प्रावधानों या संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के खिलाफ कार्य नहीं कर सकती है। [1955] 2 एस. सी. आर. 225 234-237 पर। ट्रे बनाने की शक्ति

संबंध संप्रभु शक्ति के भीतर हैं और दोनों में रहते हैं

कार्यपालिका और संसद में। संधियों और समझौतों के संबंध में कार्यपालिका क्या कर सकती है, यह सरकारी कार्य का हिस्सा है। कार्यकारी इसके द्वारा कर सकता है

एक संधि या समझौते में प्रवेश करना एक सीमा विवाद का निपटारा करता है जिसमें क्षेत्र का अधिग्रहण या हस्तांतरण शामिल नहीं होता है।

यदि बरुबारी से संबंधित समझौता नहीं होता है

यह केवल सीमा के निपटान या परिसीमन के बराबर है, फिर संसद द्वारा कला से संबंधित विधान। 3 संविधान पर्याप्त होगा लेकिन कला के तहत कानून। 368

अक्षम होगा।

संविधान का भाग I

एक स्व-निहित कोड है

संघ के क्षेत्रों से निपटना। अनुच्छेद 1 भारत के क्षेत्र को राज्यों के क्षेत्र के रूप में परिभाषित करता है; राज्यों के क्षेत्रों का विवरण भारत के क्षेत्र का वर्णन करता है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों या नए क्षेत्रों के प्रवेश द्वारा संघ के क्षेत्रों को जोड़ता है। अनुच्छेद 3 (ए) अपने अंतिम भाग में किसी भी क्षेत्र को सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के लिए एकजुट करने पर विचार करता है।

[1960]

258

किसी भी राज्य और किसी भी क्षेत्र के एक भाग में विदेशी क्षेत्र शामिल है जिसे अधिग्रहित किया जा सकता है। अनुच्छेद 3 (बी) किसी भी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि होती है जो विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण करके और इसे राज्य के क्षेत्र में जोड़कर हो सकती है। अनुच्छेद 3 (सी) किसी भी राज्य के क्षेत्र को कम करने पर विचार करता है जो किसी विदेशी शक्ति को सौंपकर हो सकता है। "वृद्धि या कमी" शब्दों पर कोई प्रतिबंध या सीमा नहीं है।

"

कला के खंड (ख) और (ग) में। 3 और वे अधिग्रहण द्वारा वृद्धि या कमी को शामिल करने के लिए पर्याप्त रूप से स्पष्ट हैं

विदेशी क्षेत्र का गठन या किसी राज्य क्षेत्र का हस्तांतरण। बाबूलाल पाराटे का मामला, [1960] 1 एस. सी. आर. 605 देखें। कला की व्याख्या में कोई भी सैद्धांतिक दृष्टिकोण या पूर्वकल्पित धारणाओं को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। 2 और 3 संविधान जैसे एक जैविक उपकरण का। कला के तहत विधान। 368 संविधान न तो आवश्यक है और न ही उचित है। कला के तहत विधान। 368 राज्यों को नुकसान होगा क्योंकि उस अनुच्छेद के तहत यह

यह आवश्यक नहीं होगा, क्योंकि यह कला के तहत होगा। 3 , अपने विचार व्यक्त करने के लिए उस राज्य को विधेयक भेजने के लिए उस पर।

कूच-बिहार परिक्षेत्रों का आदान-प्रदान नहीं होता है

समझौते को लागू करने के लिए क्षेत्र का हस्तांतरण और केवल कार्यकारी कार्रवाई ही पर्याप्त है। एक बड़े समझौते के हिस्से के रूप में प्रशासनिक विचारों के लिए क्षेत्र का आदान-प्रदान समर्पण के बराबर नहीं है। ओपेनहीम, 8 म संस्करण। , पी। 451 , कला. 169 , पी। 548 , कला. 216 , पी। 547 ; हैल्सबरी, वॉल्यूम। 7 , कला. 604. भले ही ट्रांसैक

इसमें क्षेत्र का हस्तांतरण, कला के तहत कानून शामिल है। 3 संविधान का प्रावधान समझौते को लागू करने के लिए पर्याप्त होगा।

संघ को क्षेत्र सौंपने का अधिकार है यदि और

जब अवसर आता है। इस तरह का अधिकार प्रत्येक संप्रभु राज्य में निहित है और यह तब भी निहित हो सकता है जब इसके संविधान द्वारा विशेष रूप से प्रदान नहीं किया गया हो। विलोबी, वॉल्यूम। आई, पी। 572 .

एस. एम. बोस, महाधिवक्ता, पश्चिम बंगाल, बी. सेन,

पश्चिम राज्य के लिए के. सी. मुखर्जी और पी. के. बोस

बंगाल। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत

पूरा जलपाईगुड़ी जिला अस्थायी रूप से था

पश्चिम बंगाल को दिया गया। यदि रैडक्लिफ पुरस्कार सीमा रेखा तय करता है, तो कोई विवाद नहीं हो सकता है और

समझौते की कोई आवश्यकता नहीं है।

लेकिन, अगर पुरस्कार 3 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

259

रेखा को ठीक किया और इसे अनिर्धारित छोड़ दिया, फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत, पूरा बेरूबरी पश्चिम बंगाल में चला गया। इस अधिनियम में सीमा के निपटारे पर विचार किया गया है न कि प्रधानमंत्रियों की सहमति से। यदि पुरस्कार ने सीमा तय नहीं की, तो पूरा जलपाईगुड़ी भारत का था। वास्तव में प्रधानमंत्रियों का समझौता पुरस्कार को स्पष्ट करने का कोई प्रयास किए बिना बेरूबरी को आधा-आधा विभाजित करता है। यह कहना गलत था कि समझौता केवल सीमा के सीमांकन के बराबर है। इसमें समर्पण शामिल है

पाकिस्तान के लिए भारतीय क्षेत्र। संविधान केवल विदेशी क्षेत्र हासिल करने की शक्ति देता है न कि

भारतीय क्षेत्र को विदेशी शक्तियों को सौंप दें। पहले, यह कला के तहत कार्रवाई करना आवश्यक होगा। 368

संसद को सौंपने के लिए कानून बनाने का अधिकार देना

क्षेत्र और फिर कला के तहत कानून। 3 सहारा लिया जा सकता है। कला में। 3 (क) "कोई भी क्षेत्र" शब्द विदेशी क्षेत्र को शामिल करने के लिए पर्याप्त चौड़े नहीं हैं; वे

जो पहले से ही अर्जित किया जा चुका है और बन गया है उसे लागू करें

कला के तहत संघ का हिस्सा। 1. संसद के पास केवल उस क्षेत्र के संबंध में कानून पारित करने की शक्ति है जिस पर उसका अधिकार क्षेत्र है। अनुच्छेद 3 केवल इससे संबंधित है -

राज्यों के क्षेत्रों की आंतरिक व्यवस्था और विदेशी क्षेत्र के अधिग्रहण से संबंधित नहीं है

या विदेशी शक्तियों को भारतीय क्षेत्र का समर्पण।

कृष्णा के लिए जनार्दन शर्मा के साथ एन. सी. चटर्जी

कुमार चटर्जी और रामप्रसन्ना रॉय और उनके साथ

यू. एम. त्रिवेदी, डी. आर. प्रेम, वेद व्यास, आर. थियाग्रा

जन और गणपति राय, (1) अध्यक्ष, भारतीय जनसंघ, केरल, (2) सचिव, जनसंघ, मंडी,

(3) श्री टाटा श्रीराम मूर्ति, अखिल भारतीय जन संघ, विशाखापट्टनम, (4) अध्यक्ष, भारतीय जन

संघ, मैंगलोर, (5) सचिव, भारतीय जनसंघ, सीतापुर, (6) श्री एन. थम्बन नांबियार, भारतीय

जनसंघ, थालीपरम्बु और (7) अध्यक्ष, भारतीय

जनसंघ, पट्टाम्बी (कोचीन)। प्रधानमंत्री के समझौते को बिल्कुल भी लागू नहीं किया जा सकता है। भारतीय क्षेत्र को बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता है। बेरुबाड़ी भारत संघ का एक अभिन्न अंग है और यह सब कुछ था और है।

तब से पश्चिम बंगाल के कब्जे में है

1947 में देश का विभाजन। वास्तविक प्रकृति

प्रधानमंत्रियों की सहमति यह है कि यह सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट नहीं है

[1960]

260

रैडक्लिफ पुरस्कार के अनुसार सीमा का निर्धारण, लेकिन यह पाकिस्तान को क्षेत्र सौंपने का एक शुद्ध मामला है। द स्टेट ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया बनाम में मामला दर्ज किया गया। विक्टोरिया राज्य, 12 सी. एल. आर. 667 का कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि उस मामले में किसी विदेशी शक्ति को कोई क्षेत्र देने का कोई सवाल ही नहीं था। इसी तरह, पेन वी। बाल्टीमोर, आई वेस। सेन. 444, किसी भी क्षेत्र के हस्तांतरण से संबंधित नहीं थे। वहाँ निश्चित हैं

हमारे संविधान में निहित निषेध और यह पूरी तरह से संशोधन योग्य संविधान नहीं है। संविधान की प्रस्तावना भारत के विखंडन की अनुमति नहीं देती है और भारत के भूभाग की अखंडता को संरक्षित करती है। अनुच्छेद 4, एस। 3 , पैरा। 2 , संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का एक विशिष्ट शक्ति देता है

क्षेत्र। यह जरूरी नहीं कि संप्रभुता की धारणा से यह प्रवाहित हो कि सरकार के पास अपने क्षेत्र को सौंपने की शक्ति होनी चाहिए। 33 एल. एड. 642 ; 1933 यू. एस. 258 कला में अधिग्रहण की शक्ति का स्पष्ट उल्लेख। 1 और 2 सौंपने की शक्ति को बाहर करता है। उक्ति "एक्सप्रेसियो यूनियस एक्सक्लूसिओ अल्टेरियस" क़ानूनों पर भी लागू होता है। ब्रूम्स लीगल मैक्सिम्स, 10 वीं एडन। , पी। 452 ; क्रेइज़, 5 म संस्करण। , पी। 240 ; 1951 यू. एस. 914; विलोबी, वॉल्यूम। 1 , पी। 518. भारतीय संसद

संप्रभु नहीं है और यह क्षेत्र को बदलने या विखंडित करने या कम करने से प्रतिबंधित है भारत। [1951] एस. सी. आर 744 968. प्रस्तावना निर्माताओं के दिमाग को खोलने की कुंजी है। 8 ई. आर. 1034; ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 246; [1950] एस. सी. आर. 1098. बरुबारी के क्षेत्रों को पाकिस्तान को हस्तांतरित करने में हजारों लोगों के मौलिक अधिकार शामिल हैं। मताधिकार और नागरिकता के अधिकारों को कार्यकारी कार्रवाई से नहीं खोया जा सकता है।

सी. बी. अग्रवाल और ए. जी. रत्नपर्खी,

जलपाईगुड़ी रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सचिव, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, कलकत्ता के सचिव और जलपाईगुड़ी के श्री निर्मल बोस। समझौते को कार्यकारी कार्रवाई से लागू नहीं किया जा सकता है। सरकार अपनी संपत्ति के साथ नहीं बल्कि राज्यों की संपत्ति के साथ काम कर रही है। यहाँ तक कि कला के तहत कानून भी। 3 पर्याप्त नहीं होगा। नागरिक जहाज के अधिकार को अनुच्छेद के तहत कानून के अलावा नहीं लिया जा सकता है। 11. समझौते के कार्यान्वयन में "I" के भाग III द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार

संविधान शामिल है और बरुबारी के उस हिस्से के नागरिक जो पाकिस्तान को दिए जाने हैं, ऐसे सभी अधिकारों से वंचित रहेंगे। भारत के नागरिकों को अनुच्छेद के तहत कानून बनाकर उनके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। 3. समझौते को अनुच्छेद के तहत कानून द्वारा भी लागू नहीं किया जा सकता है। 368 क्योंकि प्रस्तावना द्वारा अधिरोपित संशोधन करने की शक्ति पर सीमाएँ हैं। इस तरह के समझौते को जनमत संग्रह के माध्यम से ही लोगों की सहमति से लागू किया जा सकता है।

डी. आर. प्रेम (अदालत की अनुमति से)।

अनुच्छेद 3 नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है जैसा कि सीमांत नोट में दर्शाया गया है। अनुच्छेद 3 वर्तमान संविधान में एस के समान प्रावधान करता है। 290 भारत सरकार अधिनियम, 1935 में किया गया। दोनों आंतरिक व्यवस्था से निपटते हैं न कि

विदेशी क्षेत्र।

एम. सी. सीतलवाड़, जवाब में। का वर्णन

रैडक्लिफ पुरस्कार में सीमा रेखा स्पष्ट नहीं है और समझौते में यह प्रावधान है कि विभाजन केवल क्षैतिज होगा, इसका मतलब है कि विभाजन पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली रेखा के माध्यम से क्षेत्र को आधे से विभाजित करना है। प्रस्तावना संविधान के अनुच्छेदों की स्पष्ट भाषा को नियंत्रित नहीं कर सकती है। विलोबी, वॉल्यूम। आई, पी। 62. संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, 1952 एडन, पी। 59. प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। द.

कला की भाषा। 368 बिल्कुल स्पष्ट है और कोई सीमा नहीं है प्रस्तावना के कारण इस पर टिप्पणियां रखी जा सकती हैं। नागरिकता के अधिकार और मौलिक अधिकार

कला के तहत शक्ति को प्रभावित न करें। 368. यह केवल कला के तहत कानून द्वारा है। 2 या 3 (ए) कि विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण किया जा सकता है और भारत का हिस्सा बन सकता है। भाषा या कला के दायरे को प्रतिबंधित करने का कोई कारण या वारंट नहीं है। 3. कला का खंड (ए)। 3 स्पष्ट रूप से विदेशी क्षेत्र से संबंधित है और इसके लिए कोई वारंट नहीं है

खंड (ख) और (ग) को किसी अन्य तरीके से विदेशी क्षेत्र से संबंधित नहीं मानते हुए। प्रत्येक अन्य प्रावधान

संविधान के भाग 1 में दो प्रकार के क्षेत्र की परिकल्पना की गई है-भारतीय और विदेशी-और केवल एक प्रकार के क्षेत्र की परिकल्पना करने का कोई कारण नहीं है। ((ख), (ग), (घ) और (ङ) कला। 3. न्यायालय को यह नहीं समझना चाहिए कि

[1960]

262

इस तरह से प्रावधान जो सीमा के समायोजन को कठिन बना देगा। यह क्षेत्र को सौंपने और हासिल करने के लिए संप्रभुता का सार है। विलोबी, वॉल्यूम। आई, पीपी। 575 और 576, विलिस, पीपी। 254 255 तक। क्षेत्र के हस्तांतरण के संबंध में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।

किसी भी संविधान में। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्षेत्र को सौंपने की शक्ति इसकी संधि बनाने की शक्ति में शामिल है और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 4, धारा 3, भाग 2 द्वारा प्रदान नहीं की गई है जैसा कि श्री

एन. सी. चटर्जी। विलोबी, वॉल्यूम। आई, पी। 90. संसद को कला के तहत अधिकार दिया गया है। 11 नागरिकता के अधिकारों को छीनना। कला के तहत एक कानून। 3 और 4 "पूरक और आनुषंगिक" प्रावधानों से संबंधित होगा और इसमें कला के तहत प्रावधान हो सकते हैं। 11 नागरिकता के अधिकारों को भी छीनने के लिए। टेरी टोरी का समर्पण अनिवार्य रूप से सौंपे गए क्षेत्र के निवासियों की राष्ट्रीयता और अधिकारों को प्रभावित करता है। एनसन का नियम और संविधान की प्रथा, चौथा संस्करण। खण्ड. 2 , भाग

II, पी। 141. जब क्षेत्र के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप निष्ठा का हस्तांतरण होता है तो मौलिक अधिकार मौजूद नहीं हो सकते हैं।

कर। एड. वैल्ट।

1960. 14 मार्च। अदालत की राय थी

द्वारा घोषित

गजेन्द्रगडकर, जे.-के अनुसार

विदेश मामलों और राष्ट्रमंडल, पाकिस्तान सरकार ने दोनों देशों के बीच विवाद के 10 विषयों पर चर्चा की और उक्त विवादों के संबंध में अपने समझौते को दर्ज करते हुए एक संयुक्त नोट पर हस्ताक्षर किए और इसे अपने-अपने प्रधानमंत्रियों को प्रस्तुत किया; और तनाव के कारणों को दूर करने और समाधान करने की दृष्टि से। सीमा विवाद और भारत-पाकिस्तान सीमा क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं और उन क्षेत्रों में शांतिपूर्ण स्थिति स्थापित करने के लिए, प्रधानमंत्रियों ने अपनी-अपनी सरकारों की ओर से कार्य करते हुए, उक्त संयुक्त नोट में निर्धारित तरीके से उक्त विवादों और समस्याओं में से कुछ का समाधान करने के लिए एक समझौता किया। इस समझौते को भारत-पाकिस्तान 3 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट कहा गया है।

समझौता और इसे इसके बाद समझौते के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

वर्तमान संदर्भ में हम दो से संबंधित हैं।

समझौते के आइटम; समझौते के पैराग्राफ 2 में आइटम 3 निम्नानुसार हैः

" (3) बेरूबरी संघ सं. 12.

इसे इस तरह विभाजित किया जाएगा कि आधा क्षेत्र जी को दे दिया जाए।

पाकिस्तान, दूसरा आधा भारत से सटा हुआ है

भारत द्वारा बनाए रखा गया। बरुबारी संघ का विभाजन

नंबर 12 उत्तर से शुरू होकर क्षैतिज होगा।

देबीगंज थानाक पूर्वी कोन। विभाजन होना चाहिए

इस तरह से बनाया जाए कि कूच-बिहार पूर्वी पाकिस्तान के पचागर ठाणे के बीच के क्षेत्र

और जलपाईगुड़ी थाना के बेरूबरी संघ संख्या 12

पश्चिम बंगाल वर्तमान में जुड़ा रहेगा। भारतीय क्षेत्र के साथ और भारत के साथ रहेगा।

कूच-बिहार के बीच निचले हिस्से में घिरा हुआ है

पूर्वी पाकिस्तान और बरुबारी संघ का बोड़ा थाना नंबर 12 का आदान-प्रदान जनरल के साथ किया जाएगा।

अंतःक्षेत्रों का आदान-प्रदान और पाकिस्तान को जाएगा। "

इसी तरह समझौते की मद 10 इस प्रकार हैः

46 (10) पुराने कूच-बिहार परिक्षेत्रों का आदान-प्रदान

पाकिस्तान और पाकिस्तान के बिना भारत में घिरा हुआ है

तन, सहमत है "। ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में एक संदेह पैदा हुआ है

क्या बेरूबरी संघ से संबंधित समझौते के कार्यान्वयन के लिए किसी विधायी कार्रवाई की आवश्यकता है या कला से संबंधित संसद के उपयुक्त कानून के माध्यम से। 3 संविधान के या अनुच्छेद के प्रावधानों के

अनुसार संविधान के उपयुक्त संशोधन के माध्यम से। 368 संविधान या दोनों का; और यह कि एन्क्लेव के आदान-प्रदान से संबंधित समझौते के प्रभाव के बारे में एक समान संदेह उत्पन्न हुआ है; और यह आगे प्रतीत होता है कि बेरूबारी संघ से संबंधित समझौते के कार्यान्वयन के लिए की गई किसी भी कार्रवाई की संवैधानिक वैधता की संभावना है और साथ ही एन्क्लेव के आदान-प्रदान से संबंधित समझौते पर अदालतों में सवाल उठाए जा रहे हैं जिसमें परिहार्य और दीर्घकालिक शामिल हैं।

मुकदमा; यही कारण है कि राष्ट्रपति ने सोचा कि

कानून के जो प्रश्न उत्पन्न हुए हैं, वे इस तरह के हैं।

और इतना महत्वपूर्ण है कि यह समीचीन है कि सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1960]।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय की राय होनी चाहिए

उस पर प्राप्त किया; और इसलिए, सी. एल. द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए। (1) कला की। 143 संविधान के अनुसार, उन्होंने निम्नलिखित तीन प्रश्नों को इस न्यायालय को विचार करने और उस पर रिपोर्ट करने के लिए भेजा हैः

(1) क्या इसके लिए कोई विधायी कार्रवाई आवश्यक है

बेरू से संबंधित समझौते का कार्यान्वयन बारी यूनियन?

(2) यदि ऐसा है, तो क्या संविधान के अनुच्छेद 3 से संबंधित संसद का कोई कानून इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त है या संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान का संशोधन आवश्यक है,

जोड़ या विकल्प में?

(3) क्या संसद का एक कानून अनुच्छेद 3 से संबंधित है

के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त संविधान

परिक्षेत्रों के आदान-प्रदान से संबंधित समझौता या संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान का एक संशोधन है जिसके लिए आवश्यक है -

उद्देश्य, इसके अलावा या विकल्प में?

इस न्यायालय को इस प्रकार भेजे गए प्रश्नों पर विचार करने से पहले इतिहास को संक्षेप में प्रस्तुत करना आवश्यक है।

काल की राजनीतिक और संवैधानिक पृष्ठभूमि समझौता। 20 फरवरी, 1947 को अंग्रेजों ने

जून 1948 तक ब्रिटिश भारत में भारतीय हाथों में। उस पर 3 जून, 1947 को उक्त सरकार ने सत्ता हस्तांतरण के तरीके के बारे में एक बयान जारी किया।

प्रभावित होगी। 18 जुलाई, 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 पारित किया। यह

अधिनियम 15 अगस्त, 1947 से लागू होना था, जो नियत दिन था। नियत दिन से यह घोषित किया गया था कि दो स्वतंत्र उपनिवेशों की स्थापना भारत में की जाएगी जिन्हें क्रमशः भारत और भारत के रूप में जाना जाएगा।

पाकिस्तान। अधिनियम की धारा 2 में उप-धाराओं के प्रावधानों के अधीन रहते हुए यह प्रावधान किया गया है। (3) और (4) एस। 2 भारत के टेरी टोरी के तहत क्षेत्र होंगे

महामहिम की संप्रभुता जो नियत दिन से ठीक पहले ब्रिटिश भारत में उप-क्षेत्रों के तहत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर शामिल की गई थी। (2) एस. 2 पाकिस्तान के क्षेत्र होने थे। धारा 3,

उप-एस। (1) , बशर्ते, अन्य बातों के साथ-साथ, नियत दिन से बंगाल प्रांत का गठन

भारत सरकार अधिनियम, 1935 का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा 3 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

और उसके बदले में दो नए प्रांतों का गठन किया जाएगा जिन्हें क्रमशः पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल के रूप में जाना जाएगा। एस की उप-धारा (3)। 3 बशर्ते, अन्य बातों के साथ-साथ, नए प्रांतों की सीमाएँ

पूर्वोक्त ऐसा होगा जो नियत दिन से पहले या बाद में उस ओर से गवर्नर-जनरल जी द्वारा नियुक्त या नियुक्त सीमा आयोग के अधिनिर्णय द्वारा निर्धारित किया जा सके, लेकिन जब तक उछाल इस तरह से निर्धारित नहीं किया जाता है, (ए) इस अधिनियम की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट बंगाल जिला।

उन क्षेत्रों के रूप में माना जाएगा जो

पूर्वी बंगाल के नए प्रांत के रूप में शामिल किया जाएगा; (बी) बंगाल प्रांत में इस अधिनियम के पारित होने की तारीख को शामिल शेष क्षेत्रों को उन क्षेत्रों के रूप में माना जाएगा जो -

पश्चिम बंगाल के नए प्रांत में शामिल। धारा 3, उप-धाराएँ। (4) , बशर्ते कि "अधिनिर्णय" पद का अर्थ है, सीमा आयोग के संबंध में, आयोग के अध्यक्ष का निर्णय, जो आयोग की कार्यवाही के समापन पर गवर्नर-जनरल को अपनी रिपोर्ट में दर्ज है। पश्चिम बंगाल प्रांत को अब पश्चिम बंगाल राज्य के रूप में जाना जाता है और यह भारत का एक हिस्सा है, जबकि पूर्वी बंगाल प्रांत पाकिस्तानी तान का हिस्सा बन गया है और अब इसे पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता है।

बेरुबारी संघ संख्या 12, जिसके बारे में हम चिंतित हैं।

एड, का क्षेत्रफल 8.75 वर्ग किलोमीटर है। मीलों और दस से बारह हजार निवासियों की आबादी। यह स्थित है

जलपाई गुड़ी जिले का जलपाईगुड़ी पुलिस थाना, जो उस समय राजा शाही प्रभाग का एक हिस्सा था। हालाँकि, इसे स्वतंत्रता अधिनियम की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट नहीं किया गया है, और यदि इस मामले पर उक्त अनुसूची के आलोक में विचार किया जाना है, तो यह पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा होगा। लेकिन, जैसा कि हम वर्तमान में इंगित करेंगे, स्वतंत्रता अधिनियम की पहली अनुसूची वास्तव में लागू नहीं हुई थी।

30 जून, 1947 को गवर्नर-जनरल ने एक

घोषणा की कि यह निर्णय लिया गया है कि बंगाल और पंजाब प्रांत का विभाजन किया जाएगा। तदनुसार, बंगाल के लिए एक सीमा आयोग नियुक्त किया गया था, जिसमें उच्च न्यायालयों के चार न्यायाधीश और एक अध्यक्ष को बाद में नियुक्त किया गया था।

सर सिरिल रैडक्लिफ को बाद में अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जहाँ तक बंगाल का संबंध है, मेत रियाल संदर्भ शर्तों में यह प्रावधान था कि सीमा आयोग को मुसलमानों और गैर-मुसलमानों के सन्निहित क्षेत्रों का पता लगाने के आधार पर बंगाल के दो हिस्सों की सीमाओं का सीमांकन करना चाहिए; ऐसा करने में उसे अन्य कारकों को भी ध्यान में रखना था। आयोग ने तब अपनी जांच की और 12 अगस्त, 1947 को एक पुरस्कार दिया, जिसे रैडक्लिफ पुरस्कार (जिसे इसके बाद पुरस्कार कहा जाता है) के रूप में जाना जाता है। यह.

यह ध्यान दिया जाएगा कि यह पुरस्कार स्वतंत्रता अधिनियम के तहत नियत दिन से तीन दिन पहले दिया गया था। रिपोर्ट से पता चलता है कि सभापति ने सात बुनियादी प्रश्न तैयार किए जिनके निर्णय पर पूर्व-पश्चिम बंगाल के बीच सीमा रेखा का सीमांकन निर्भर था। प्रश्न संख्या 6 हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है। इसे इस तरह से तैयार किया गया थाः

" सी. 6. दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों के संबंध में किस राज्य का दावा प्रबल होना चाहिए, जिसमें दार्जिलिंग के मामले में मुस्लिम आबादी कुल आबादी का 2.42% और जलपाईगुड़ी के मामले में कुल आबादी का 23-08% थी, लेकिन जो किसी भी प्राकृतिक अर्थ में बंगाल के दूसरे गैर-मुस्लिम क्षेत्र के अनुकूल क्षेत्र नहीं था? ” ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग के सदस्य किसी भी मुद्दे पर सहमत होने में असमर्थ थे।

प्रमुख मुद्दे, और इसलिए अध्यक्ष के पास अपना निर्णय देने के लिए आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तदनुसार सभापति ने प्रासंगिक मुद्दों पर अपना निर्णय इन शब्दों में दियाः

" सीमा रेखा का सीमांकन है

अनुसूची में विस्तार से लिखा गया है जो बनता है

पुरस्कार के लिए अनुलग्नक ए और उससे संलग्न मानचित्र में, अनुलग्नक बी. मानचित्र चित्रण के उद्देश्यों के लिए संलग्न किया गया है, और यदि अनुलग्नक ए में वर्णित सीमा के बीच कोई विचलन होना चाहिए और जैसा कि अनुलग्नक बी में मानचित्र पर चित्रित किया गया है, तो अनुलग्नक ए में विवरण हैः

विजय प्राप्त करें "।

अनुलग्नक ए में अनुच्छेद 1 सामग्री है। इसमें प्रावधान किया गया है कि "सीमा के साथ एक रेखा दार्जिलिंग जिले में फान्सीदेवा के थाना और 3 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्टों के जिले में थाना तेतुलिया के बीच खींची जाएगी।

जलपाईगुड़ी उस बिंदु से जहां वह सीमा बिहार प्रांत से मिलती है और फिर तेतुलिया और राजगंज के थानों, पचागर और राजगंज के थानों और पचागर और जलपाईगुड़ी के थानों के बीच की सीमा के साथ, और फिर देबीगंज के थानों के उत्तरी कोने के साथ कूच-बिहार राज्य की सीमा तक जारी रहेगी। दार्जिलिंग जिला और जलपाईगुड़ी जिले का इतना हिस्सा इस रेखा के उत्तर में स्थित है

पश्चिम बंगाल, लेकिन पटग्राम का थाना और कोई भी

जलपाईगुड़ी जिले का अन्य हिस्सा जो पूर्व या दक्षिण में स्थित है, पूर्वी बंगाल का होगा। चूंकि यह पुरस्कार स्वतंत्रता अधिनियम के तहत नियुक्त दिन से तीन दिन पहले लागू हुआ था, इसलिए पश्चिम बंगाल प्रांत का क्षेत्रीय विस्तार कभी भी उक्त स्वतंत्रता अधिनियम की अनुसूची I के तहत निर्धारित नहीं किया गया था, लेकिन यह पुरस्कार द्वारा निर्धारित किया गया था। इस बात में कोई विवाद नहीं है कि पुरस्कार की तारीख से बेरू बारी संघ संख्या 12 वास्तव में राज्य का हिस्सा बन गया है।

पश्चिम बंगाल और इस तरह से शासित किया गया है।

इस बीच संविधान सभा जो शुरू हुई

9 दिसंबर, 1946 को इसके विचार-विमर्श को भारत के लिए संप्रभु संविधान सभा के रूप में फिर से इकट्ठा किया गया।

14 अगस्त, 1947 की मध्यरात्रि में इसने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने का अपना ऐतिहासिक कार्य शुरू किया। एक मसौदा

संविधान द्वारा समिति नियुक्त की गई थी

विधानसभा और उसके द्वारा तैयार किया गया मसौदा 4 नवंबर, 1948 को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उचित विचार-विमर्श के बाद मसौदे को तीन रीडिंग से पारित किया गया और अंतिम रूप दिए जाने पर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

विधानसभा और 26 नवंबर, 1949 को पारित घोषित। उस तारीख को यह संविधान बन गया

भारत; लेकिन, जैसा कला द्वारा प्रदान किया गया है। 394 , उस तारीख से केवल निर्दिष्ट अनुच्छेद लागू हुए और शेष प्रावधान 26 जनवरी, 1950 से लागू हुए।

संविधान में इस दिन को शुरुआत के रूप में संदर्भित किया गया है

संविधान का। संविधान का अनुच्छेद 1 यह प्रावधान करता है कि भारत, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा और राज्य और

राज्य और उनके क्षेत्र इसके राज्य क्षेत्र होंगे।

प्रथम के भाग ए, बी और सी में निर्दिष्ट टोरी

अनुसूची. पश्चिम बंगाल को एक के रूप में दिखाया गया था

भाग ए में राज्य; और यह प्रावधान किया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1960]

पश्चिम बंगाल राज्य के क्षेत्र में वह क्षेत्र शामिल होगा जो संविधान की शुरुआत से ठीक पहले -

पश्चिम बंगाल का प्रांत। पुरस्कार के आलोक में बेरूबरी संघ संख्या 12 को पश्चिम बंगाल प्रांत का एक हिस्सा माना गया था और इस आधार पर व्यवहार और शासन किया गया है।

इसके बाद, भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ सीमा विवाद उत्पन्न हुए और 14 दिसंबर, 1948 को नई दिल्ली में आयोजित अंतर-डोमिनियन सम्मेलन में उनके बीच यह सहमति बनी कि उक्त विवादों के निर्णय और अंतिम निर्णय के लिए बिना किसी देरी के और किसी भी मामले में 31 जनवरी, 1949 के बाद एक न्यायाधिकरण का गठन किया जाना चाहिए। इस न्यायाधिकरण को भारत-पाकिस्तान सीमा विवाद न्यायाधिकरण के रूप में जाना जाता है और इसकी अध्यक्षता की गई थी। माननीय लॉर्ड जस्टिस अल्गोट बागे द्वारा। इस न्यायाधिकरण को पूर्व-पश्चिम बंगाल के संबंध में कई विवादों पर विचार करना पड़ा, लेकिन इस अवसर पर बेरू बारी संघ के बारे में कोई मुद्दा नहीं उठाया गया। वास्तव में न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही में जलपाईगुड़ी जिले का कोई संदर्भ नहीं दिया गया था। बागे पुरस्कार 26 जनवरी, 1950 को दिया गया था। यह दो साल बाद था जब 1952 में पहली बार पाकिस्तान सरकार द्वारा बेरुबारी संघ का सवाल उठाया गया था। इस पूरी अवधि के दौरान बेरूबरी संघ भारतीय संघ के कब्जे में बना रहा और पश्चिम बंगाल के एक हिस्से के रूप में शासित था। 1952 में पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि पुरस्कार के तहत बरुबारी संघ को वास्तव में पूर्वी बंगाल का हिस्सा बनना चाहिए था और इसे गलत तरीके से पश्चिम बंगाल का हिस्सा माना गया था। जाहिरा तौर पर इस विषय पर भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच समय-समय पर सुलह होती रही और यह विवाद 1958 तक बना रहा। इन परिस्थितियों में ही दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच 10 सितंबर, 1958 को वर्तमान समझौता हुआ था। यही बरुबारी संघ संख्या 12 के संबंध में वर्तमान विवाद की पृष्ठभूमि है।

इस स्तर पर हम संक्षेप में उन घटनाओं का भी उल्लेख कर सकते हैं जिनके कारण अंततः भारत और पाकिस्तान के बीच कूच-बिहार परिक्षेत्रों का प्रस्तावित आदान-प्रदान हुआ। भारत सरकार की धारा 290 3 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

अधिनियम, 1935 में प्रावधान किया गया था कि महामहिम द्वारा

ऑर्डर-इन-काउंसिल किसी भी क्षेत्र को बढ़ाएँ या घटाएँ

प्रांत या किसी भी प्रांत की सीमा में परिवर्तन

सामान्य आधार कि भारत सरकार थी अतिरिक्त-प्रांतीय क्षेत्राधिकार अधिनियम द्वारा प्राधिकृत

उस संबंध में आवश्यक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए 1947 का अधिनियम।

इसके बाद 12 जनवरी, 1949 को राज्य सरकार ने भारत अधिनियम, 1935 में संशोधन किया गया। 290 ए और

एस. 290 इसमें बी जोड़ा गया था। धारा 290-ए पढ़ता है

इस प्रकारः

स्वागत है।

" 290 - ए. कुछ अधिग्रहण का प्रशासन

राज्यपाल या मुख्य आयुक्त के प्रो का हिस्सा विंसः

(1) जहाँ पूर्ण और अनन्य अधिकार, न्यायशास्त्र

शासन के लिए और उसके संबंध में राज्य और शक्तियाँ

किसी भी भारतीय राज्य या ऐसे राज्यों के किसी समूह का कुछ समय के लिए डोमिनियन द्वारा प्रयोग किया जा सकता है

सरकार, गवर्नर-जनरल आदेश द्वारा प्रत्यक्ष

(क) कि राज्य या राज्यों का समूह होगा

सभी मामलों में प्रशासित जैसे कि राज्य या

राज्यों का समूह मुख्य आयुक्त का समर्थक था

विनस; या

(ख) कि राज्य या राज्यों का समूह होगा

सभी मामलों में प्रशासित जैसे कि राज्य या

राज्यपाल का हिस्सा बने राज्यों का समूह या

में निर्दिष्ट मुख्य आयुक्त का प्रांत

आदेश; "।

धारा 290-बी (1) में प्रावधान है कि गवर्नर-जीन

राज्यपाल के प्रांत या एक मुख्य आयुक्त के प्रांत के भीतर एक स्वीकृति राज्य द्वारा शामिल क्षेत्र, और यह निर्धारित करता है कि स्वीकृति क्षेत्र होगा किसी पड़ोसी राज्य द्वारा सभी मामलों में इस तरह से प्रशासित किया जाता है जैसे कि ऐसा क्षेत्र ऐसे राज्य का हिस्सा है, और उसके बाद सरकार के प्रावधान -

भारत अधिनियम तदनुसार लागू होगा।

इन दोनों खंडों के बाद इस प्रकार कई खंड जोड़े गए

भारत सरकार द्वारा भारतीय राज्यों के भारत संघ में विलय के लिए कदम उठाए गए थे।

इस उद्देश्य के साथ राज्यों के विलय (राज्यपालों के पक्ष में) आदेश, 1949,27 जुलाई, 1949 को पारित किया गया था। इस आदेश का प्रभाव यह था कि जिन राज्यों ने

प्रांतों के साथ विलय को हर तरह से प्रशासित किया जाना था जैसे कि वे अवशोषित प्रांतों का हिस्सा हों। इस आदेश में समय-समय पर संशोधन किया गया था। समय। 28 अगस्त, 1949 को भारत सरकार और कूच-बिहार राज्य के शासक के बीच विलय का समझौता हुआ।

पुर

इस समझौते के बाद भारत सरकार ने 12 सितंबर, 1949 को कूच-बिहार का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया और इस प्रकार कूच-बिहार इसका हिस्सा बन गया।

भारत के क्षेत्र का और तदनुसार शामिल किया गया था।

संविधान की पहली अनुसूची में क्रम संख्या 4 के रूप में भाग सी राज्यों की सूची में। इसके बाद, दिसंबर में

31, 1949 से राज्यों के विलय (पश्चिम बंगाल) आदेश, 1949 पारित किया गया था। यह प्रदान करता है कि जबकि पूर्ण और

भारतीय राज्य के शासन के लिए और उसके संबंध में अनन्य प्राधिकरण, अधिकार क्षेत्र और शक्ति

कूच-बिहार का उपयोग डोमिनियन द्वारा किया जा सकता था सरकार, आदेश द्वारा प्रदान करना समीचीन था

एस के तहत बनाया गया। 290 ए सभी मामलों में उक्त राज्य के प्रशासन के लिए जैसे कि यह प्रो का हिस्सा है पश्चिम बंगाल का विंस। परिणामस्वरूप, 1 जनवरी, 1950 को पूर्ववर्ती कूच-बिहार राज्य का विलय कर दिया गया।

पश्चिम बंगाल के साथ और यह पश्चिम बंगाल के हिस्से के रूप में शासित होने लगा। इस विलय के परिणामस्वरूप कूच बिहार को संविधान की पहली अनुसूची में भाग सी राज्यों की सूची से बाहर कर दिया गया और उसी अनुसूची में पश्चिम बंगाल में जोड़ा गया।

पहली अनुसूची में निर्धारित पश्चिम बंगाल के विवरण में उस खंड को जोड़कर संशोधन किया गया था जिसमें उन क्षेत्रों को संदर्भित किया गया था जो प्रशासित किए जा रहे थे जैसे कि वे उस प्रांत का हिस्सा थे। दूसरे शब्दों में, कूच-बिहार के विलय के बाद पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में वे क्षेत्र शामिल थे जो संविधान के प्रारंभ से पहले पश्चिम बंगाल प्रांत में शामिल थे।

साथ ही जो प्रशासित किए जा रहे थे जैसे कि वे उस प्रांत का हिस्सा थे। इसके बाद पश्चिम के क्षेत्रों में एक और जोड़ किया गया है।

बंगाल में चंदेरनगर को शामिल किया गया है, लेकिन इस स्तर पर उक्त जोड़ का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।

ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ क्षेत्र जिनका हिस्सा था

पूर्व भारतीय राज्य कूच बिहार के क्षेत्र और जो बाद में भारत और फिर पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों का हिस्सा बन गए थे

यह पाकिस्तान में विभाजन एन्क्लेव के बाद बना।

इसी तरह कुछ पाकिस्तानी एन्क्लेव पाए गए थे

भारत। अस्तित्व से उत्पन्न होने वाली समस्या

पाकिस्तान और भारत में इन परिक्षेत्रों के साथ-साथ अन्य सीमा समस्याओं पर भारत और पाकिस्तान की सरकारों द्वारा लंबे समय से विचार किया जा रहा था। पाकिस्तान में भारत के इन परिक्षेत्रों और भारत में पाकिस्तान के अस्तित्व ने दोनों देशों के बीच तनाव और संघर्ष के निरंतर स्रोत के रूप में काम किया। तनाव और संघर्ष के इन कारणों को दूर करने के लिए दोनों प्रधानमंत्रियों ने उक्त परिक्षेत्रों की समस्या को हल करने और उक्त क्षेत्रों में शांतिपूर्ण स्थिति स्थापित करने का निर्णय लिया। यह इस उद्देश्य के साथ है कि अंतःक्षेत्रों के आदान-प्रदान पर उनके द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी और उक्त समायोजन का वर्णन समझौते के पैराग्राफ 3 के आइटम 10 में किया गया है। कि संक्षेप में इसकी ऐतिहासिक और संवैधानिक पृष्ठभूमि है

परिक्षेत्रों का आदान-प्रदान।

भारत संघ की ओर से विद्वान अटार

एन. ई.-जनरल ने तर्क दिया है कि बेरूबरी संघ से संबंधित समझौते के कार्यान्वयन के साथ-साथ परिक्षेत्रों के आदान-प्रदान के लिए कोई विधायी कार्रवाई आवश्यक नहीं है। बरुबारी संघ के संबंध में उनका तर्क है कि समझौते का उद्देश्य सटीक सीमा का पता लगाना या उसका सीमांकन करना है।

जिसके द्वारा दोनों देशों के बीच विवाद मौजूद था उनके द्वारा रखी गई विभिन्न व्याख्याओं का कारण

पुरस्कार में निहित प्रासंगिक विवरण; उक्त समझौता केवल उस सीमा की मान्यता या निर्धारण है जो पहले से ही तय की जा चुकी थी और

इसका कोई मतलब नहीं है कि यह एक नई सीमा का प्रतिस्थापन है या

सीमा का परिवर्तन जो किसी भी परिवर्तन का संकेत देता है

भारत की क्षेत्रीय सीमाएँ। वह इस बात पर जोर देते हैं कि

सीमा का निर्धारण या निपटान उस पुरस्कार के आलोक में जिसके द्वारा दोनों सरकारें

बाध्य थे, एक अलगाव या समर्पण नहीं है

भारत का क्षेत्र, और उसके अनुसार, यदि, परिणामस्वरूप

प्रकाश में वास्तविक सीमा का निर्धारण

पुरस्कार के अनुसार, कुछ भूमि का कब्जा 272 होना चाहिए।

पाकिस्तान को सौंप दिया गया यह समर्पण के बराबर नहीं है

क्षेत्र; यह केवल उछाल को निपटाने का एक तरीका है। पुरस्कार ने पहले ही सीमा का निपटारा कर दिया था; लेकिन चूंकि उक्त सीमा के स्थान के संबंध में दोनों सरकारों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ था, इसलिए पुरस्कार द्वारा दिए गए निर्देशों और मानचित्रों के आलोक में विवाद का समाधान किया गया था।

उससे जुड़ा हुआ है। जहाँ सीमा के बारे में विवाद हो इस प्रकार दो राज्यों के बीच उत्पन्न होता है और यह उन पर बाध्यकारी एक निर्णय के आलोक में हल किया जाता है-जो समझौता इस तरह के विवाद के निपटारे का प्रतीक है, उसे उनके बीच वास्तविक सीमा का पता लगाने के अलावा और कुछ नहीं माना जाना चाहिए और इसे किसी के पक्ष में क्षेत्र के हस्तांतरण या अलगाव के रूप में नहीं माना जा सकता है।

दूसरे से। इस तर्क के अनुसार,

न तो सीमा का वास्तविक परिवर्तन और न ही क्षेत्र का वास्तविक विभाजन, और संविधान की पहली अनुसूची में पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों के विवरण में कोई परिवर्तन या परिवर्तन करने का कोई अवसर नहीं होगा।

यह विद्वान वकील द्वारा भी मामूली रूप से सुझाया गया है।

सामान्य तौर पर यह कि कूच-बिहार एन्क्लेव्स का आदान-प्रदान बेरूबरी संघ के बारे में सामान्य और व्यापक समझौते का एक हिस्सा है और वास्तव में यह इसके लिए आकस्मिक है। इसलिए, उक्त संदर्भ में देखा जाए तो, यह भी

यह नहीं कहा जा सकता कि विनिमय में किसी का समर्पण शामिल है।

क्षेत्र।

इस धारणा पर विद्वान महान्यायवादी

उन्होंने आगे तर्क दिया है कि समझौता और पुनर्कथन

वास्तविक सीमा का निर्धारण केवल कार्यकारी कार्रवाई से ही किया जा सकता है, और इसलिए दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच जो समझौता हुआ है

बिना किसी विधायी कार्रवाई के लागू किया जा सकता है।

इस तर्क के समर्थन में विद्वान वकील

जनरल ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर भरोसा किया है और हम इस स्तर पर उनका संक्षिप्त रूप से उल्लेख कर सकते हैं।

सातवीं अनुसूची की सूची I में प्रविष्टि 14 इस प्रकार है -

इस प्रकारः " विदेशों के साथ संधियों और समझौतों में प्रवेश करना और विदेशों के साथ संधियों, सहमतियों और सम्मेलनों को लागू करना।

" "

अनुच्छेद 253 भाग 11 में आता है जो संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है।

यह 3 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट प्रदान करता है।

273

कि "उक्त अध्याय के पूर्वगामी उपदर्शनों में किसी बात के होते हुए भी संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ किसी संधि, समझौते या संधि या किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संघ या अन्य निकाय में किए गए किसी भी निर्णय को लागू करने के लिए भारत के पूरे या किसी भाग के लिए कोई कानून बनाने की शक्ति है।" यह शक्ति संसद को प्रविष्टि 14 के संदर्भ में प्रदान की गई है। इसके अलावा एक ही भाग में तीन अन्य लेख हैं जो प्रासंगिक हैं। अनुच्छेद 245 (1) संसद को पूरे या क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है।

भारत; अनुच्छेद 245 (2) में प्रावधान है कि संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून अमान्य नहीं माना जाएगा।

इस आधार पर कि इसका अतिरिक्त-क्षेत्रीय संचालन होगा; अनुच्छेद 246 उस विषय को निर्धारित करता है-कानून का विषय जो संसद बना सकती है; और अनुच्छेद। 248 संसद में विधान की अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 248 में कहा गया है कि संसद को समवर्ती सूची या राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कोई भी कानून बनाने की शक्ति है। इस प्रकार किसी अन्य देश के साथ किसी भी संधि, समझौते या समझौते के बारे में कानून बनाने और इस तरह के समझौते को प्रभावी बनाने के लिए संसद की विधायी क्षमता के बारे में कोई संदेह नहीं है।

समझौता या समझौता।

हालाँकि, यह आग्रह किया जाता है कि निर्माण के संबंध में

संधियों को लागू करना और उन्हें कार्यपालिका द्वारा केंद्र सरकार की शक्तियाँ संसद की शक्तियों के साथ-साथ व्यापक और सह-आनुषंगिक हैं। यह तर्क कुछ अनुच्छेदों के प्रावधानों पर आधारित होने की कोशिश की जाती है, जिनके लिए संदर्भ दिया जा सकता है।

अनुच्छेद 53 (1) में प्रावधान है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और

संविधान के अनुसार उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या उसके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद 73, जिस पर मजबूत निर्भरता रखी गई है, संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा निर्धारित करता है। अनुच्छेद 73 (1) में कहा गया है कि "इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, संघ की कार्यकारी शक्ति (ए) उन मामलों तक विस्तारित होगी जिनके संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति है; और (बी) ऐसे अधिकारों, प्राधिकरण और न्यायशास्त्र के प्रयोग के लिए।

जो किसी संधि या समझौते के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते कि सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1960]

274

उप-क्ल में निर्दिष्ट कार्यकारी शक्ति। ((क) इस संविधान में या संविधान में स्पष्ट रूप से उपबंध किए जाने के अलावा, ऐसा नहीं होगा।

संसद द्वारा बनाई गई कोई भी विधि, किसी भी राज्य में उन मामलों तक विस्तारित होती है जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल को भी विधि बनाने की शक्ति है; और अनुच्छेद 74 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों के प्रयोग में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधान मंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी; और अनुच्छेद 74 (2) में कहा गया है कि यह प्रश्न कि क्या कोई है, और यदि हां, तो मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को क्या सलाह दी गई थी, किसी भी अदालत में इसकी जांच नहीं की जाएगी। विद्वान महान्यायवादी के अनुसार-शक्तियाँ

कला के तहत संघ कार्यकारी को प्रदान किया गया। 73 (1) (ए) संदर्भ द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का संदर्भ है

सातवीं अनुसूची में प्रविष्टि 14, सूची I, जबकि कला द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ। 73 (1) (ख) अनुच्छेद द्वारा संसद को प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप हैं।

253 संविधान से। वास्तव में विद्वान महान्यायवादी ने तर्क दिया कि यह स्थिति इस न्यायालय के एक निर्णय से समाप्त होती है। राय साहब राम जवाया

कपूर और ओआरएस। वी. पंजाब राज्य (1) भारतीय संविधान के तहत कार्यकारी सरकार किन सीमाओं के भीतर काम कर सकती है, इस सवाल से निपटने के लिए मुख्य न्यायाधीश मुखर्जी, जिन्होंने न्यायालय का सर्वसम्मत निर्णय दिया, ने कहा है कि "उक्त सीमाओं को कार्यपालिका के रूप के संदर्भ में बिना किसी कठिनाई के निर्धारित किया जा सकता है जो हमारे संविधान ने स्थापित किया है", और कहा है कि "कार्यकारी कार्य में दोनों शामिल हैं -

नीति के निर्धारण के साथ-साथ इसे निष्पादित करना। इसमें स्पष्ट रूप से कानून की शुरुआत, व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना, विदेश नीति की दिशा, वास्तव में राज्य के सामान्य प्रशासन का संचालन या पर्यवेक्षण शामिल है। इसी अवलोकन पर विद्वान महान्यायवादी ने अपने तर्क को स्थापित किया है।

आइए पहले विचार करें कि समझौते ने वास्तव में क्या किया है। क्या यह वास्तव में निर्णय के आलोक में सीमाओं को निर्धारित करने के लिए अभिप्रेत है, या उसने विवादित क्षेत्र को आधा-आधा विभाजित करके तदर्थ आधार पर विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने की कोशिश की है? समझौते के प्रासंगिक भाग को पढ़कर यह कहा गया है कि

(1) [1955] एस. सी. आर. 225।

275

इस निष्कर्ष से बचना मुश्किल है कि पक्षों को

यह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सबसे समीचीन

और विवाद को हल करने का उचित तरीका होगा

क्षेत्र को आधे और आधे में विभाजित करें। वहाँ

समझौते में हस्तक्षेप करने के किसी भी प्रयास का कोई निशान नहीं है

पुरस्कार की तैयारी करें या यह निर्धारित करें कि वास्तव में पुरस्कार क्या है

मतलब। समझौता इस कथन के साथ शुरू होता है कि

यह निर्णय कि विवादित क्षेत्र इतना विभाजित होगा

भारत द्वारा बनाए रखे जाने के निकट। अन्य में शब्दों में, समझौता कहता है कि, हालांकि पूरे

बेरुबारी संघ संख्या 12 का क्षेत्र भारत के भीतर था।

भारत इसका आधा हिस्सा पाकिस्तान को देने के लिए तैयार था। दोस्ताना संबंध सुनिश्चित करने के लिए देने और लेने की भावना

पक्षों के बीच संबंध बनाना और उनके बीच तनाव के कारणों को दूर करना। इस निर्णय पर पहुंचने के बाद

समझौता बताता है कि निर्णय कैसे लिया जाना चाहिए।

बाहर निकलें। यह प्रावधान करता है कि क्षेत्र का विभाजन होगा

डेबी के उत्तर-पूर्वी कोने से शुरू होने वाला क्षैतिज

गंज थाना। इसमें यह भी प्रावधान है कि विभाजन इस तरह से किया जाना चाहिए कि कूच-बिहार एन्क्लेव हो जाएं।

पूर्वी पाकिस्तान के पचागर ठाणे और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी ठाणे के बेरू बारी संघ संख्या 12 के बीच भारत के पास रहेगा। यह फिर से आधे क्षेत्र को विभाजित करने के निर्णय को पूरा करने के लिए एक प्रावधान है। फिर भी, पूर्वी पाकिस्तान के बोड़ा थाना और बेरूबरी संघ के बीच निचले हिस्से में स्थित कूच-बिहार क्षेत्र के विभाजन के बारे में एक और प्रावधान किया गया है।

सं. 12 और यह प्रावधान किया गया है कि एन्क्लेव के सामान्य आदान-प्रदान के साथ उनका आदान-प्रदान किया जाएगा और वे पाकिस्तान जाएंगे। हमारी राय में, इस समझौते के प्रत्येक खंड से स्पष्ट और स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अधिनिर्णय के अलावा, और स्वतंत्र रूप से, क्षेत्र को आधे और आधे में विभाजित करने पर सहमति हुई थी और इस विभाजन को लागू करने की विधि उस ओर से चार भौतिक प्रावधान करके इंगित की

गई थी। यदि ऐसा है, तो इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है कि समझौते का यह हिस्सा समझौते के निर्धारण और चित्रण से अधिक कुछ नहीं है। पुरस्कार के प्रकाश में सीमाएँ।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह विद्वान वकील द्वारा सुझाया गया है

सामान्य तौर पर 276 में विवरण की जांच

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1960]

पुरस्कार के संबंध में अनुसूची में अनुलग्नक ए

पुलिस स्टेशन की सीमाओं से इसमें एक कमी का पता चला,

क्योंकि इसमें उछाल का कोई उल्लेख नहीं था

पुलिस स्टेशन बोड़ा और पुलिस स्टेशन के बीच झगड़ा

जलपाईगुड़ी; और तर्क यह है कि इसका परिणाम

वर्णन यह था कि दो बिंदु निर्दिष्ट किए गए थे, एक

बेरुबारी संघ की पश्चिमी सीमा पर (

थानों के बीच की सीमा की चरम सीमा

पचागर और जलपाईगुड़ी) और दूसरा इसके पूर्व में

सीमा (देवी के थाना का उत्तरी कोना)

गंज जहाँ यह कूच-बिहार राज्य से मिलता है) बिना दिए

मानचित्र में खींचा गया, अनुसूची में अनुलग्नक बी पुरस्कार, यदि विवरण से स्वतंत्र रूप से पालन किया जाता है

संघ पूर्वी बंगाल के क्षेत्र में गिर गया होगा और यह सरकार द्वारा किया गया दावा था

पाकिस्तान, और यह वह दावा है जिसका निपटारा किया गया था

पुरस्कार की रोशनी।

इस संबंध में यह याद रखना प्रासंगिक है कि

सभापति द्वारा विशेष रूप से दिए गए निर्देश यह पुरस्कार कि नक्शा इस उद्देश्य के लिए संलग्न किया गया है

उदाहरण और यह कि मानचित्र, अनुलग्नक बी और अनुलग्नक ए में वर्णित सीमा के बीच किसी भी विचलन के मामले में, अनुलग्नक ए में विवरण प्रबल होना चाहिए, और इसलिए रेखा के बल पर पूर्वी बंगाल में लगभग पूरे बरुबारी संघ को शामिल करने के लिए कोई भी दावा उचित या वैध रूप से नहीं किया जा सकता है।

मानचित्र में चित्रित। इसके अलावा, जिस कमी का विद्वान महान्यायवादी उल्लेख करता है, वह हो सकती थी

सीमा निर्धारित करने में पुरस्कार द्वारा अपनाई गई सामान्य विधि को ध्यान में रखते हुए ठीक किया जाता है। अनुलग्नक ए में पैरा ग्राफ 3 से पता चलता है कि पुरस्कार द्वारा तय की गई रेखा आम तौर पर थानों के बीच की सीमाओं के साथ आगे बढ़ती थी, और पुरस्कार की इस सामान्य रेखा ने विवाद के निर्णय में सहायता की होगी यदि इसका उद्देश्य विवाद को हल करना था। जिस रेखा को अनुलग्नक ए के पैराग्राफ 1 में खींची जानी थी, उसे थाना देवी गंज के उत्तरी कोने से लेकर कूच-बिहार राज्य की सीमा तक जारी रखना है और 3 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट।

इस संदर्भ में यह सुझाव दिया जा सकता है कि इसे संबंधित थानों की सीमाओं के संदर्भ में जोड़ा जाना था। यह मुख्य रूप से इन मान्यताओं के कारण है कि विचाराधीन क्षेत्र भारत के कब्जे में कुछ वर्षों तक था।

पुरस्कार और 1952 तक कोई विवाद नहीं उठाया गया था।

हमने एम्फा के लिए इन तथ्यों का उल्लेख किया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि समझौता इन तथ्यों को ध्यान में रखने के बाद नहीं हुआ है और यह पुरस्कार की व्याख्या और इसके प्रभाव के आधार पर किसी भी निष्कर्ष पर आधारित नहीं है। वास्तव में समझौते का दूसरा खंड जो यह निर्देश देता है कि बेरूबरी संघ संख्या 12 का विभाजन देवीगंज ठाणे के उत्तर-पूर्व कोने से शुरू होकर क्षैतिज होगा, बहुत खुशी से नहीं कहा गया है। "होरी" शब्द का उपयोग

ज़ोंटल "थोड़ा अनुचित प्रतीत होता है; लेकिन, इसके अलावा, इस क्षैतिज के रूप में दिशा

विभाजन के तरीके के साथ-साथ समझौते में निहित अन्य दिशाएं उस निष्कर्ष से निकलती हैं जिसके साथ समझौता शुरू होता है कि यह निर्णय लिया गया था कि भारत को पाकिस्तान को आधा क्षेत्र देना चाहिए। हमने समझौते के सभी खंडों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और हम संतुष्ट हैं कि यह पुरस्कार और इसकी शर्तों की किसी भी व्याख्या के परिणामस्वरूप नहीं हुआ है और न ही हुआ है; यह पुरस्कार से स्वतंत्र रूप से और उन कारणों और विचारों के लिए किया गया है जो पक्षों को बुद्धिमान और समीचीन लगे। इसलिए, हम विद्वान महान्यायवादी द्वारा आग्रह किए गए तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि यह कानून के आलोक में सीमाओं का पता लगाने और निर्धारित करने के अलावा और कुछ नहीं करता है। पुरस्कार। यह एक ऐसा समझौता है जिसके द्वारा भारत के क्षेत्र का एक हिस्सा पाकिस्तान को सौंप दिया गया है और इसलिए इस समझौते के संबंध में हमें संदर्भित प्रश्न पर इस आधार पर विचार किया जाना चाहिए कि इसमें भारत के क्षेत्र के एक हिस्से का हस्तांतरण या अलगाव शामिल है।

क्षेत्र।

इस संबंध में समझौते के बारे में क्या सच है

कूच-बिहार एन्क्लेव्स के आदान-प्रदान के बारे में बेरूबरी संघ संख्या 12 अभी भी अधिक दृढ़ता से सच है। वास्तव में विद्वान अटॉर्नी-जनरल का तर्क कि नहीं

इस आदान-प्रदान के संबंध में समझौते को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाना आवश्यक है

यह कि यह आदान-प्रदान एक बड़े और व्यापक समझौते का हिस्सा है और इसलिए यह अपने चरित्र में भाग लेता है। चूंकि हमारा मानना है कि बेरूबरी संघ संख्या 12 के संबंध में समझौते में ही भारत के क्षेत्र का हस्तांतरण शामिल है।

कूच-बिहार एन्क्लेव्स के आदान-प्रदान में भारतीय क्षेत्र का हस्तांतरण शामिल है। यही कारण है कि

इस आदान-प्रदान के बारे में सवाल पर भी भारत के क्षेत्र के एक हिस्से के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। पाकिस्तान को सौंप दिया गया है; इसके अलावा यह स्पष्ट है कि प्रश्न 1 और 2 के विपरीत तीसरा प्रश्न जो इस आदान-प्रदान का संदर्भ देता है, कानून की आवश्यकता को स्वीकार करता है।

इस संबंध में हम दूसरे से भी निपट सकते हैं।

विद्वान महान्यायवादी द्वारा आग्रह किया गया तर्क। उन्होंने तर्क दिया कि बेरूबरी संघ के संबंध में समझौते के कार्यान्वयन के लिए संविधान की पहली अनुसूची में किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि उनके अनुसार, बेरूबरी संघ को उक्त अनुसूची में निहित पश्चिम बंगाल के क्षेत्रीय विवरण में कभी भी कानूनी रूप से शामिल नहीं किया गया था। हम नहीं हैं।

इस तर्क से भी प्रभावित। जैसा कि हम पहले ही संकेत दे चुके हैं, चूंकि पुरस्कार की घोषणा बेरूबरी में की गई थी

संघ भारत के कब्जे में रहा है और

हमेशा पश्चिम बंगाल के एक हिस्से के रूप में माना जाता है और इस तरह से शासित। इस तथ्यात्मक स्थिति को देखते हुए

यह मानने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि यह उन क्षेत्रों के भीतर आता है जो इससे ठीक पहले

संविधान का प्रारंभ शामिल था

पश्चिम बंगाल प्रांत में। नतीजतन,

इस समझौते के कार्यान्वयन की सीमा पश्चिम बंगाल के रागों में बदलाव किया जाएगा और विषय-वस्तु

संविधान की पहली अनुसूची में प्रविष्टि 13

प्रभावित होंगे।

इस विषय पर चर्चा करने से पहले हमें इसका उल्लेख करना चाहिए -

दक्षिण ऑस्ट्रेलिया राज्य बनाम में ऑस्ट्रेलियाई उच्च न्यायालय का निर्णय। विक्टोरिया राज्य (1) जिस पर

विद्वान वकील द्वारा निर्भरता रखी गई है जनरल। उस स्थिति में राज्य के बीच की सीमा

दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स राज्य

अधिनियम 4 और 5 वसीयत द्वारा। IV, c. 95 और लेटर्स पेटेंट

उस अधिनियम के तहत जारी किया गया जिसे 141 वीं मेरिडियन के रूप में परिभाषित किया गया है

(1) (1911) 12 सीएलआर 667।

पूर्वी देशांतर। 1847 में, न्यू साउथ वेल्स और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के राज्यपालों के अधिकार से

और राज्य सचिव की जानकारी और अनुमोदन के साथ एक रेखा स्थित थी और जमीन पर 141 वें मेरिडियन के रूप में चिह्नित की गई थी, लेकिन 1869 में यह पता चला कि उक्त रेखा वास्तव में उस मेरिडियन के पश्चिम की ओर लगभग दो मील की दूरी पर थी। हालाँकि, 1847 में चिह्नित रेखा को संबंधित राज्यपालों द्वारा सीमा के रूप में घोषित किया गया था और यह वास्तविक सीमा थी।

{

सीमा वहाँ से आगे। दोनों राज्यों के बीच वास्तविक सीमा के संबंध में उत्पन्न हुए विवाद से निपटने में, सी. जे. ग्रिफिथ ने 1847 में सीमा के निर्धारण का उल्लेख किया और कहा कि "वास्तविक लेन-देन किसी तथ्य का पता लगाने के लिए सक्षम व्यक्तियों द्वारा इसका पता लगाना है, और इस तरह से किए गए तथ्य का निष्कर्ष, और दोनों द्वारा स्वीकार किया गया, उन पर बाध्यकारी होने में एक पुरस्कार या निर्णय की प्रकृति में है और

उनके अधीन दावा करने वाले सभी व्यक्ति "(पृ. 701)। ने कहा कि बाद में विवाद को प्रिवी काउंसिल में ले जाया गया

और यह प्रिवी काउंसिल द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था कि

लेटर्स पेटेंट का वास्तविक निर्माण यह असंगत था

प्लेटेड कि 141 वें मेरिडियन की सीमा रेखा

पूर्वी देशांतर का पता लगाया जाना चाहिए और उसका प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए

पृथ्वी की सतह पर ताकि एक सीमा बनाई जा सके

दो उपनिवेशों को विभाजित करने वाली रेखा, और इसलिए यह दोनों उपनिवेशों की कार्यपालिका को निहित रूप से दिया गया

ऐसे कार्य करने की शक्ति जो परम के लिए आवश्यक थे

धीरे-धीरे ऐसी सीमाओं को तय करना "(1)। प्रिवी काउंसिल

यह भी देखा गया कि "भौतिक तथ्यों से पता चलता है कि

दोनों सरकारों ने पूरी सावधानी के साथ एक ईमानदार जितना संभव हो सके उतना निकटता से प्रतिनिधित्व करने का प्रयास

ए द्वारा लेटर्स पेटेंट द्वारा निर्धारित रेटिक सीमा पृथ्वी की सतह पर सीमांकन की व्यावहारिक रेखा।

वहाँ से जाने के किसी भी इरादे का कोई निशान नहीं है निर्दिष्ट सीमा, लेकिन केवल इसे पुनः पेश करने के लिए, और के रूप में

अपनी प्रकृति में यह एक का गंभीर दर्जा होना था

उनके प्रभुत्त्वों को अधिकार क्षेत्र की सीमा में कोई संदेह नहीं है

कि यह दो अधिकारियों द्वारा तय किया जाना था

अंत में वैधानिक सीमा के रूप में और वह बिंदु में

कानून के अनुसार यह इतना तय था "। इस प्रकार यह स्पष्ट होगा कि

सीमाओं का निपटान जो आयोजित नहीं किया गया था

उस मामले में एक अलगाव की राशि थी

(1) [1914] ए. सी. 283,309

पूरी तरह से संदर्भ द्वारा बनाया गया, और के प्रकाश में,

संसदीय कानून का प्रावधान जो संदर्भित करता है

एनस पहले ही बनाया जा चुका है। क्या किया गया था 1847 उन पक्षों द्वारा जिनसे निपटने का अधिकार था

मामला एक रेखा का पता लगाने और चिह्नित करने का था

जो मैदान 141 वां मेरिडियन माना जाता था

हालांकि यह सच है कि 1869 में यह पता चला था कि इस तरह से तय की गई रेखा पश्चिम की ओर लगभग दो मील दूर थी।

मेरिडियन से। यह ऐसा मामला नहीं था जहां अनुबंध किया गया हो। दलों ने स्वतंत्र रूप से एक के साथ रेखा निर्धारित की

दोनों के बीच विवाद को निपटाने का दृष्टिकोण

राज्यों। वे क्या करना चाहते थे यह निर्धारित करने के लिए था

संसदीय कानून। वर्तमान मामले में, जैसा कि हम पहले ही इंगित कर चुके हैं, सहमति की स्थिति

विचार अनिवार्य रूप से अलग है; इसका उद्देश्य नहीं है

के मामले में निर्णय से कोई सहायता दक्षिण ऑस्ट्रेलिया राज्य बनाम। विक्टोरिया राज्य (1)

समझौते के निर्माण के लिए उनका समर्थन।

हमारे निष्कर्ष को देखते हुए कि समझौता

भारतीय राज्य के किसी हिस्से का समर्पण या अलगाव

क्षेत्र और यह केवल सीमा का निर्धारण या निर्धारक राष्ट्र नहीं है, और पुरस्कार के संदर्भ में, विद्वान अटॉर्नी-जनरल द्वारा उठाए गए अन्य विवाद पर विचार करना आवश्यक नहीं है। कि इस तरह के समझौते में प्रवेश करना संघ निष्पादन की क्षमता के भीतर था, और यह कि समझौते को बिना किसी कानून के लागू किया जा सकता है

यह। उनके द्वारा यह उचित रूप से स्वीकार किया गया है कि यह

तर्क इस धारणा पर आगे बढ़ता है कि सहमति सार और तथ्य में निर्णय द्वारा पहले से ही निर्धारित विवादित सीमा के निर्धारण या निर्धारण से अधिक नहीं है। इसलिए, हमें कार्यकारी कार्यों और शक्तियों के चरित्र और विस्तार के बारे में तर्क के गुण-दोष पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है और न ही हमें इस प्रश्न की जांच

करने की आवश्यकता है कि क्या राय साहब राम जवाया कपूर (2) के मामले में मुखर्जी, सी. जे. द्वारा की गई टिप्पणियां वास्तव में उक्त तर्क का समर्थन करती हैं, और यदि वे करती हैं, तो क्या प्रश्न पर पुनर्विचार नहीं किया जाना चाहिए।

(1) [1911] 12 सीएलआर 667।

(2) [1955] 2 एस. सी. आर. 225

281

इस स्तर पर गुणों पर विचार करना आवश्यक है।

श्री चटर्जी द्वारा हमारे सामने उठाए गए प्रतिद्वंद्वी विवाद के बारे में। वे आग्रह करते हैं कि संसद को भी भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से को किसी विदेशी राज्य के पक्ष में या तो साधारण कानून द्वारा या यहां तक कि संविधान के संशोधन द्वारा सौंपने की कोई शक्ति नहीं है; और इसलिए, उनके अनुसार, केवल एक ही राय हम संदर्भ पर दे सकते हैं।

यह है कि समझौता अमान्य है और नहीं हो सकता है

किसी भी विधायी प्रक्रिया द्वारा भी प्रभावी बनाया जाए। यह चरम विवाद दो आधारों पर आधारित है। यह सुझाव दिया जाता है कि संविधान की प्रस्तावना स्पष्ट रूप से मानती है कि लोकतांत्रिक गणराज्य की तरह

संसद की पहुंच से बाहर है और नहीं हो सकता है या तो साधारण विधान द्वारा या यहाँ तक कि द्वारा प्रभावित

श्री चटर्जी कहते हैं कि भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में गठित करने का गंभीरता से संकल्प लिया गया है। मूल रूप से हमेशा लोकतांत्रिक और गणतंत्रवादी बने रहना चाहिए। जिस दूसरे आधार पर यह विवाद उठाया गया है, वह कला पर आधारित है। 1 (3) (ग) संविधान का जो विचार करता है कि "का क्षेत्र

भारत में ऐसे अन्य क्षेत्र शामिल होंगे जिनका अधिग्रहण किया जा सकता है और यह तर्क दिया जाता है कि जहां संविधान ने देश को स्पष्ट रूप से अन्य क्षेत्रों का अधिग्रहण करने की शक्ति दी है, वहीं उसने अपने क्षेत्र के किसी भी हिस्से को सौंपने का कोई प्रावधान नहीं किया है। निर्माण के नियम का मामला, अर्थात। , विशिष्ट परिवर्तन लागू होना चाहिए। हमारी राय में, इन विवादों में कोई सार नहीं है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि द्वारा की गई घोषणा

भारत के लोग संविधान की प्रस्तावना में अपनी संप्रभु इच्छा का प्रयोग करते हुए, शब्दों में,

ओरी, "निर्माताओं के दिमाग को खोलने की कुंजी"

जो उन सामान्य उद्देश्यों को दिखा सकते हैं जिनके लिए उन्होंने संविधान में कई प्रावधान किए थे; लेकिन सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1960]

फिर भी प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, और जैसा कि विलोबी ने अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना के बारे में कहा है, "इसे कभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार या उसके किसी भी विभाग को प्रदान की गई किसी भी ठोस शक्ति का स्रोत नहीं माना गया है। इस तरह की शक्तियों में केवल वे शामिल हैं जो संविधान के मुख्य भाग में स्पष्ट रूप से प्रदान की गई हैं और जो इस तरह से प्रदान की गई शक्तियों से निहित हो सकती हैं। शक्तियों के बारे में जो सच है वह निषेधों और सीमाओं के बारे में भी उतना ही सच है। इसके अलावा, यह नहीं है

फिर, इस तर्क के संबंध में कि प्राप्त करने की शक्ति को शामिल करने से अनिवार्य रूप से त्याग करने या अलग करने की शक्ति को बाहर कर दिया जाना चाहिए, दो स्पष्ट उत्तर हैं। अनुच्छेद 1 (3) (सी) भारत को क्षेत्रों का अधिग्रहण करने की शक्ति या अधिकार प्रदान नहीं करता है। चटर्जी मान लेते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत संप्रभुता के दो आवश्यक अधिकार विदेशी क्षेत्र हासिल करने की शक्ति के साथ-साथ एक विदेशी राज्य के पक्ष में राष्ट्रीय क्षेत्र को सौंपने की शक्ति है। क्या कला है। 1 (3) (ग) करने का उद्देश्य एक औपचारिक प्रावधान करना है

किसी भी विदेशी क्षेत्र का अवशोषण और एकीकरण जो भारत द्वारा अपने अंतर्निहित अधिकार के आधार पर अधिग्रहित किया जा सकता है। यह हो सकता है कि इस प्रावधान को संविधान में किसी भी विस्तारवादी राजनीतिक दर्शन के अनुसरण में नहीं, बल्कि मुख्य रूप से 3 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्टों के एकीकरण और अवशोषण के लिए स्थान मिला है।

भारतीय क्षेत्र जो संविधान की तारीख तक विदेशी राज्यों के प्रभुत्व में बने रहे; लेकिन यह कला का पूरा दायरा नहीं है। 1 (3) (सी)। यह मोटे तौर पर उन सभी विदेशी क्षेत्रों को संदर्भित करता है जो

भारत द्वारा अधिग्रहित किया जाएगा और यह प्रावधान किया जाएगा कि जैसे ही उनका अधिग्रहण किया जाएगा वे भारत के भूभाग का हिस्सा बन जाएंगे। इस प्रकार, कला के वास्तविक निर्माण पर। 1 (3) (ई) यह मान लेना गलत है कि यह विदेशी क्षेत्रों को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट शक्तियां प्रदान करता है। द. विवाद का दूसरा जवाब कला द्वारा प्रदान किया गया है। 368 संविधान से। उस लेख के लिए प्रदान करता है

संविधान के संशोधन के लिए प्रक्रिया और उस ओर से संसद को स्पष्ट रूप से शक्ति प्रदान करता है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति में अनिवार्य रूप से अनुच्छेद में संशोधन करने की शक्ति शामिल होनी चाहिए। 1 , और इसमें तार्किक रूप से किसी विदेशी राज्य के पक्ष में राष्ट्रीय क्षेत्र को सौंपने की शक्ति शामिल होगी; और यदि ऐसा है, तो यह तर्क देना अनुचित होगा कि भारत के संप्रभु राज्य में अपने क्षेत्र को सौंपने की कोई शक्ति नहीं है और भारत के मामले में राष्ट्रीय क्षेत्र को सौंपने की शक्ति का अभाव है जो संप्रभुता का एक आवश्यक लक्षण है। इसलिए, हमें श्री चटर्जी के इस तर्क को अस्वीकार करना चाहिए कि कोई भी विधायी प्रक्रिया संबंधित समझौते को मान्य नहीं कर सकती है।

तो फिर संधि बनाने की प्रकृति क्या है?

एक संप्रभु राज्य की शक्ति? यही अगला प्रो है

जिस दोष पर हमें अपनी राय के लिए भेजे गए प्रश्नों पर खुद को संबोधित करने से पहले विचार करना चाहिए।

जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि यह एक आवश्यक कार्य है। संप्रभुता जो एक संप्रभु राज्य प्राप्त कर सकता है

विदेशी क्षेत्र और आवश्यकता पड़ने पर, अपने क्षेत्र का एक हिस्सा किसी विदेशी राज्य के पक्ष में सौंप सकता है, और यह अपनी संधि बनाने की शक्ति का उपयोग करके किया जा सकता है। कानूनी राशियों में राष्ट्रीय क्षेत्र का समर्पण

उक्त क्षेत्र पर संप्रभुता के हस्तांतरण के लिए स्वामी द्वारा-दूसरे राज्य के पक्ष में राज्य। वहाँ।

इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि इस तरह का समर्पण संभव है और

विलेख का इतिहास इसके कई उदाहरण प्रस्तुत करता है

यह देखा गया कि "कठिनाई इस तथ्य में शामिल है कि समर्पण के सभी मामलों में क्षेत्र के निवासी

जो अपनी पुरानी नागरिकता खो देते हैं और उन्हें सौंप दिया जाता है

एक नए संप्रभु को, चाहे वे इसे पसंद करें या सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1960]

(1) नहीं; और उन्होंने इंगित किया है कि "निवासियों को सौंपे जाने के आरोप को टालने के साधन के रूप में सौंपे गए क्षेत्र के निवासियों के पक्ष में एक निश्चित अवधि के भीतर प्रवास करने का विकल्प निर्धारित करके इस कठिनाई को कम करना संभव हो सकता है।

उनकी इच्छा के विरुद्ध एक नए संप्रभु को सौंप दिया गया "(पी। 553)। लेकिन हालांकि मानवीय दृष्टिकोण से महान कठिन जहाज अनिवार्य रूप से एक देश द्वारा दूसरे देश को क्षेत्र के हस्तांतरण में शामिल है, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि एक संप्रभु राज्य अपने क्षेत्र का एक हिस्सा विदेशी राज्य को सौंपने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। यह शक्ति, इसे जोड़ा जा सकता है, निश्चित रूप से उन सीमाओं के अधीन है जो राज्य का संविधान या तो स्पष्ट रूप से या उस संबंध में आवश्यक निहितार्थ द्वारा लागू कर सकता है; दूसरे शब्दों में, यह सवाल कि राष्ट्रीय क्षेत्र के हस्तांतरण के संबंध में एक संप्रभु राज्य द्वारा संधियां कैसे की जा सकती हैं और जब संधियां की जा सकती हैं तो उन्हें कैसे लागू किया जा सकता है, देश के संविधान के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। मोटे तौर पर कहा गया है कि संधि बनाने की शक्ति का प्रयोग संविधान द्वारा विचारित तरीके से और उसके द्वारा लगाई गई सीमाओं के अधीन किया जाना चाहिए। की गई संधि को सामान्य कानून द्वारा या संवैधानिक संशोधन द्वारा लागू किया जा सकता है, यह स्वाभाविक रूप से संविधान के प्रावधानों पर निर्भर करेगा। इसलिए, अब हमें समस्या के उस पहलू की ओर मुड़ना चाहिए और अपने संविधान के तहत स्थिति पर विचार करना चाहिए।

इस पहलू से निपटने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं

यह धारणा कि कुछ कानून की आवश्यकता है

विचाराधीन समझौते को लागू करें। भारत संघ की ओर से यह आग्रह किया जाता है कि यदि समझौते के कार्यान्वयन के लिए कोई विधायी कार्रवाई आवश्यक मानी जाती है तो संसद का एक कानून जो कला से संबंधित हो। 3 संविधान की धारा इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त होगी और यदि ऐसा है, तो अनुच्छेद के तहत कोई कार्रवाई करने का कोई अवसर नहीं होगा। 368 संविधान से। इस प्रश्न का निर्णय अनिवार्य रूप से कला के निर्माण पर निर्भर करेगा। 3 स्वयं। विद्वान महान्यायवादी ने हमें संविधान की मूल संरचना की विशेष विशेषताओं को ध्यान में रखने के लिए कहा है।

(1) लॉटरपैक्ट द्वारा ओपेनहेम का "अंतर्राष्ट्रीय कानून", खंड। मैं,

पी. 55 1. (8 टी एड।)

कला के सुसंगत प्रावधानों के निर्माण में शिक्षा। 3 . उनका तर्क है कि कॉन्स्टी की मूल संरचना

शिक्षा भारत सरकार अधिनियम, 1935 के समान है, जिसने पहली बार भारत में एक संघीय राजनीति की शुरुआत की थी। अन्य संघों के विपरीत, उक्त अधिनियम में सन्निहित संघ नहीं था

राज्यों के अलग और स्वतंत्र समुदायों के बीच एक समझौते या संघ का परिणाम जो कुछ सामान्य उद्देश्यों के लिए एक साथ आए और अपनी संप्रभुता के एक हिस्से को आत्मसमर्पण कर दिया। संघ की घटक इकाइयों को जानबूझकर बनाया गया था और यह महत्वपूर्ण नहीं है कि अन्य संघों की इकाइयों के विपरीत, अतीत में उनकी कोई जैविक जड़ें नहीं थीं। इसलिए, भारतीय संविधान में, अन्य संघीय संविधानों के विपरीत

संविधान में, घटक राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता के संरक्षण पर जोर नहीं दिया गया है। संविधान के निर्माता उन विशिष्ट परिस्थितियों से अवगत थे जिनके तहत राज्यों (मूल रूप से प्रांतों) का गठन किया गया था।

और उनकी सीमाओं को परिभाषित किया गया था, और इसलिए उन्होंने कला में प्रावधानों को अपनाया। 3 एक दृश्य के साथ

भारतीय राज्यों के एकीकरण के बाद उक्त क्षेत्रों के पुनर्वितरण की संभावना को पूरा करने के लिए। वास्तव में यह सर्वविदित है कि राज्यों के परिणामस्वरूप

पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम XXXVII)

मूल 27 राज्यों और एक क्षेत्र का स्थान जिसका उल्लेख पहली अनुसूची में भाग डी में किया गया था

संविधान, अब केवल 14 राज्य और 6 अन्य हैं

उल्लिखित केंद्र शासित प्रदेश का गठन करने वाले क्षेत्र

पहली अनुसूची में। इस प्रकार परिवर्तन स्पष्ट रूप से किए गए

विशिष्ट और हड़ताली के काम को चित्रित करें

भारतीय संविधान की विशेषता। हो सकता है

इस विवाद में कुछ बल। इसलिए यह हो सकता है

माना कि कला के निर्माण में। 3 हमे लेना चाहिए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि संविधान ने विचार किया

घटक की क्षेत्रीय सीमाओं में परिवर्तन

राज्य और उनके क्षेत्र के बारे में कोई गारंटी नहीं थी

टोरियल इंटीग्रिटी।

संविधान का भाग I संघ से संबंधित है और

इसके क्षेत्र, और एक अर्थ में इसके प्रावधान एक निर्धारित करते हैं

उक्त विषय के संबंध में स्व-निहित कोड। जैसे-जैसे भाग II नागरिकता के विषय से संबंधित है, भाग I से संबंधित है

[1960]

भारत के क्षेत्र के साथ। कला. 1 नाम के बारे में

और भारत का क्षेत्र। वह इस प्रकार हैः —

" 1. (1) भारत, अर्थात भारत, एक संघ होगा

राज्यों।

(2) राज्य और उनके क्षेत्र होंगे -

जैसा कि पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है।

(3) भारत के क्षेत्र में शामिल होंगे

((क) राज्यों के क्षेत्र;

(ख) पहले में निर्दिष्ट केंद्र शासित प्रदेश

अनुसूची; और

((ग) ऐसे अन्य क्षेत्र जिनका अधिग्रहण किया जा सकता है।

" "

कला. 1 जैसा कि अब है, संशोधनों का परिणाम है।

संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम द्वारा बनाया गया,

1956. इसके संशोधन से पहले, कला। मैंने उल्लेख किया कि

भारत का क्षेत्र जिसमें क्षेत्र शामिल हैं भाग ए, बी और सी के साथ-साथ परिक्षेत्र में निर्दिष्ट राज्य

अनुसूची के भाग डी में विनिर्दिष्ट स्रोत और इस तरह के क्षेत्र जिनका अधिग्रहण किया जा सकता है। फिर एक अलग

प्रावधान कला द्वारा किया गया था। 243 भाग IX में इसके लिए

भाग डी में निर्दिष्ट क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों जैसे कि नए अधिग्रहित क्षेत्रों का प्रशासन

जो पहली अनुसूची में शामिल नहीं थे। द. 1956 के संविधान संशोधनों ने कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

चींटी कला में परिवर्तन करती है। 1. के बीच अंतर

भाग ए, बी और सी और भाग में निर्दिष्ट क्षेत्र

डी को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर विशिष्टता आई

राज्यों और संघ के क्षेत्रों के बीच की स्थिति पहली अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्र। कॉन्स में

क्वेंस आर्ट। 243 भाग IX को हटा दिया गया था। वह यह है कि

कैसे वर्तमान अनुच्छेद के तहत का क्षेत्र

भारत में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और ऐसे अन्य क्षेत्रों के क्षेत्र शामिल हैं जिनका अधिग्रहण किया जा सकता है। हम पहले ही कला का उल्लेख कर चुके हैं। 1 (3) (ग) और हमने देखा है कि यह प्रदान करने के लिए अभिप्रेत नहीं है भारत पर क्षेत्रों का अधिग्रहण करने की शक्ति; यह केवल समर्थक है

स्वचालित अवशोषण या ए. एस. आई. के लिए कार्य करता है और पहचानता है भारत के क्षेत्र में क्षेत्रों का एकीकरण जो

विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण करने के लिए एक संप्रभु राज्य के रूप में अपने अंतर्निहित अधिकार के आधार पर भारत द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। इस प्रकार कला। 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है और इसके क्षेत्रों को निर्दिष्ट करता है।

अनुच्छेद 2 में प्रावधान है कि संसद कानून द्वारा

संघ में प्रवेश या ऐसे 3 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्टों पर नए राज्यों की स्थापना

नियम और शर्तें जो वे उचित समझते हैं। इस अनुच्छेद से पता चलता है कि विदेशी क्षेत्र जो अधिग्रहण के बाद भारत के क्षेत्र का हिस्सा बन जाएंगे

कला. 1 (3) (ग) कानून द्वारा कला के तहत संघ में प्रवेश दिया जा सकता है। 2. ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश किया जा सकता है संघ या नए राज्यों में ऐसे नियमों और शर्तों पर गठित किया जा सकता है जो संसद सोचे

और जैसा कि हम वर्तमान में ऐसे क्षेत्रों को इंगित करेंगे

कला के तहत कानून द्वारा भी निपटा जा सकता है। 3 (ए) या (बी)। कला में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "कानून द्वारा"। 2 और 3 इंच यह संबंध महत्वपूर्ण है। एक संप्रभु राज्य के रूप में अपने अंतर्निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए भारत द्वारा विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण स्वचालित रूप से

उक्त क्षेत्र भारत के क्षेत्र का एक हिस्सा है। इस प्रकार ऐसे क्षेत्र के अधिग्रहण और तथ्यात्मक रूप से भारत के क्षेत्र का हिस्सा बनाए जाने के बाद कानून की प्रक्रिया

इसे या तो कला के तहत आत्मसात करें। 2 या कला के तहत। 3 3 (ए) या (बी)।

प्रक्रिया के एक उदाहरण के रूप में जो हो सकता है

नव अधिग्रहित क्षेत्र को अवशोषित करने के लिए एक कानून बनाने में संसद द्वारा अपनाया गया हम चंद्रनगर विलय अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम XXXVI) का उल्लेख कर सकते हैं, जिसे 29 सितंबर, 1954 को पारित किया गया था और

2 अक्टूबर, 1954 से बल। चंदननगर, जो

एक फ्रांसीसी अधिकार था, एक स्वतंत्र शहर घोषित किया गया था, और जून 1946 में फ्रांसीसी सरकार, समझौते में

भारत सरकार ने कहा कि उसका इरादा भारत में फ्रांसीसी प्रतिष्ठानों के लोगों को अपने भविष्य के बारे में घोषणा करने का अधिकार छोड़ना है और

भविष्य की स्थिति। इस घोषणा के अनुसरण में ए

1949 में चंदेरनगर में जनमत संग्रह हुआ था, और

इस जनमत संग्रह में चंदेरनगर के नागरिकों ने मतदान किया भारत के साथ क्षेत्र के विलय का पक्ष लेना।

नतीजतन, 2 मई, 1950 को राष्ट्रपति ने

फ्रांसीसी गणराज्य ने एक वास्तविक हस्तांतरण को प्रभावित किया

भारत में चंदेरनगर का प्रशासन, और उस तारीख को भारत सरकार ने नियंत्रण ग्रहण किया था

और एस के तहत चंदननगर पर अधिकार क्षेत्र। 4 में से विदेशी क्षेत्राधिकार अधिनियम, 1947 (1947 का अधिनियम 47)। रीले।

भारत उक्त धारा के तहत जिसके परिणामस्वरूप सी. आर. इस पर भारतीय कानून लागू किए गए थे। ने कहा कि

अधिसूचना में यह भी प्रावधान किया गया है कि संबंधित सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1960]

288 फ्रांसीसी कानून 2 मई, 1950 से लागू नहीं होंगे। इसके बाद पेरिस में सेसियन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए और नियत समय पर 9 जून, 1952 को उक्त संधि के अनुसमर्थन पर चंदेरनगर को भारत सरकार को न्यायिक रूप से हस्तांतरित कर दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि चंदेरनगर एक फ्रांसीसी क्षेत्र नहीं रह गया और भारत के भूभाग का हिस्सा बन गया और विदेशी क्षेत्राधिकार अधिनियम अब उस पर लागू नहीं था। अनुच्छेद 243 (1) जो उस समय चलन में था, 9 जून, 1952 से चंदेरनगर पर लागू हुआ और कला के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया गया। 243 (2) राष्ट्रपति ने चंदननगर के प्रशासन के लिए एक विनियमन जारी किया जो

30 जून, 1952 से बल। भारत सरकार ने तब एक जांच आयोग नियुक्त करके चंदरनगर के नागरिकों की इच्छाओं का पता लगाया, और आयोग की रिपोर्ट प्राप्त करने पर कि चंदरनगर के लोग लगभग सर्वसम्मति से पश्चिम बंगाल के साथ विलय के पक्ष में थे, सरकार ने संसद में चंदरनगर विलय अधिनियम की शुरुआत की। इस अधिनियम के पारित होने के बाद 2 अक्टूबर, 1954 से चंदननगर का पश्चिम बंगाल राज्य में विलय हो गया। यह अधिनियम संसद द्वारा अनुच्छेद के तहत पारित किया गया था। 3 संविधान से। इस अधिनियम के परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल की सीमाओं को अनुच्छेद के तहत बदल दिया गया था। 3 ((घ) और एस द्वारा। 4 संविधान की पहली अनुसूची को संशोधित किया गया था। इस प्रकार हमने संक्षेप में उल्लेख किया है कि

चंदर नागौर के अधिग्रहण और अवशोषण और पश्चिम बंगाल के साथ इसके विलय का इतिहास क्योंकि कला के संचालन को महत्वपूर्ण रूप से दर्शाता है। I (3) (c) के साथ-साथ कला। 3 ((ख) और (घ) संविधान।

यह हमें कला की ओर ले जाता है। 3 जो नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन के विषय से संबंधित है; लेकिन इससे पहले कि हम कला का अर्थ लगाएँ। 3 कला का उल्लेख करना सुविधाजनक होगा। 4 . अनुच्छेद 4 इस प्रकार कहता हैः --

“ 4. (1) अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी भी कानून में संशोधन के लिए ऐसे प्रावधान होंगे।

पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के जो कानून के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो और इसमें ऐसे पूरक, आनुषंगिक और परिणामी प्रावधान भी शामिल हो सकते हैं (जिसमें संसद में प्रतिनिधित्व के प्रावधान और 3 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट शामिल हैं)।

राज्य के विधानमंडल या विधानमंडलों में या ऐसे कानून से प्रभावित राज्य) जिन्हें संसद समझे

आवश्यक है।

(2) उपरोक्त किसी भी कानून को ऐसा नहीं माना जाएगा -

उद्देश्यों के लिए इस संविधान का संशोधन। अनुच्छेद 368 "।

कला का प्रभाव। 4 यह है कि कानून कला से संबंधित हैं। 2 ° या कला। 3 इन्हें कला के उद्देश्य के लिए संवैधानिक संशोधन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। 368 , जिसका अर्थ है कि यदि विधान कला के तहत सक्षम है। 3 समझौते के संबंध में, कला का आह्वान करना अनावश्यक होगा। 368. दूसरी ओर, यह समान रूप से स्पष्ट है कि यदि प्रासंगिक विषय के संबंध में कानून कला के तहत आवश्यक नहीं है। 3 , कला. 368 अनिवार्य रूप से लागू होगा। इसलिए, समस्या का मूल बिंदु हैः क्या संसद अनुच्छेद के तहत समझौते के संबंध में कानून बना सकती है? 3 ?

आइए अब आर्ट पढ़ें। 3. वह इस प्रकार हैः " कला. 3. संसद कानून द्वारा कर सकती है

(क) क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य बनाना।

किसी राज्य से या दो या दो से अधिक राज्यों को एकजुट करके या राज्यों के भागों या किसी क्षेत्र को एक भाग में मिलाकर

किसी भी राज्य का;

((ग) किसी भी राज्य के क्षेत्र को कम करना। ((घ) किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना;

((ङ) किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन;

बशर्ते कि इस उद्देश्य के लिए कोई विधेयक नहीं होगा

संसद के किसी भी सदन में पेश किया गया सिवाय इसके कि

राष्ट्रपति की सिफारिश और जब तक कि,

जहाँ विधेयक में निहित प्रस्ताव प्रभावित करता है - किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमाएँ या नाम। . .

विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा भेजा गया है

अपने विचार व्यक्त करने के लिए उस राज्य का विधानमंडल

उस पर ऐसी अवधि के भीतर जो निर्दिष्ट की जाए संदर्भ या ऐसी आगे की अवधि के भीतर जैसे कि

राष्ट्रपति अनुमति दे सकते हैं और इस प्रकार निर्दिष्ट अवधि

या अनुमति समाप्त हो गई है।

प्रथम दृष्टया कला। 3 ऐसा प्रतीत हो सकता है कि

समस्याएँ जो भाषाई या किसी अन्य आधार पर भारत के घटक राज्यों के पुनर्गठन पर उत्पन्न होंगी; लेकिन यह कला का पूरा दायरा नहीं है। 3 . मोटे तौर पर कहा गया है कि यह आंतरिक समायोजन से संबंधित है।

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट के घटक राज्यों के क्षेत्रों के बीच [1960]

भारत। अनुच्छेद 3 (ए) संसद को एक नया राज्य बनाने में सक्षम बनाता है और यह या तो किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके, या दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के कुछ हिस्सों को एकजुट करके, या किसी भी क्षेत्र को किसी भी राज्य के एक हिस्से में एकजुट करके किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि विदेशी क्षेत्र जो अधिग्रहण के बाद कला के तहत भारत के क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है। 1 (3) (ग) कला के अंतिम खंड में शामिल है। 3 (क) और यह कि ऐसा क्षेत्र, उसके अधिग्रहण के बाद, उस नए राज्य में अवशोषित किया जा सकता है जिसका गठन अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है। 3 (ए)। इस प्रकार कला। 3 (क) एक नए राज्य के गठन की समस्या से संबंधित है और उन तरीकों को इंगित करता है जिनके द्वारा

नया राज्य बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 3 (बी) में प्रावधान है कि किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए कानून पारित किया जा सकता है। यह वृद्धि राज्यों के पुनर्गठन के लिए आकस्मिक हो सकती है, जिस स्थिति में कला के तहत एक राज्य में जोड़ा जाता है। 3 ((ख) हो सकता है कि उसे किसी अन्य राज्य के क्षेत्र से निकाला गया हो। कला द्वारा परिकल्पित किसी भी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि। 3 ((ख) यह अनुच्छेद में निर्दिष्ट क्षेत्र के किसी भी भाग को किसी भी राज्य में जोड़ने का परिणाम भी हो सकता है। 1 (3) (सी)। अनुच्छेद 3 (डी) किसी भी राज्य की सीमाओं के परिवर्तन को संदर्भित करता है और ऐसा परिवर्तन कला में निर्दिष्ट किसी भी समायोजन का परिणाम होगा। 3 (ए), (बी) या (सी)। अनुच्छेद 3 (ई) जो किसी भी राज्य के नाम के परिवर्तन को संदर्भित करता है, कोई कठिनाई प्रस्तुत नहीं करता है, और वास्तव में उन प्रश्नों पर कोई सामग्री नहीं है जिनसे हम संबंधित हैं। हमें अभी कला पर विचार करना है। 3 (ग) जिसका निर्माण संदर्भ के तहत प्रश्नों के उत्तर प्रदान करेगा; लेकिन इससे पहले कि हम कला की व्याख्या करें। 3 (ग) हम उक्त अनुच्छेद से संबंधित एक पहलू का उल्लेख करना चाहेंगे जिसे

पूरा। यह महत्वपूर्ण है कि कला। 3 संदर्भ में यह केंद्र शासित प्रदेशों को संदर्भित नहीं करता है और इसलिए, वे कला के अंतिम खंड में शामिल हैं या नहीं। 3 ((क) इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे कला के दायरे से बाहर हैं। 3 (ख), (ग), (घ) और (ङ)। दूसरे शब्दों में, यदि केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों में वृद्धि या कमी है यदि उनकी सीमाओं या नामों में परिवर्तन प्रस्तावित किया जाता है, तो इसे कला से संबंधित कानून द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता है। 3. यह स्थिति काफी महत्वपूर्ण होगी।

कला की व्याख्या में सहायता। 3 (सी)।

अनुच्छेद 3 (सी) ह्रास की समस्या से संबंधित है।

किसी भी राज्य के क्षेत्र का। इस तरह की कमी तब हो सकती है जब किसी राज्य के क्षेत्र के हिस्से को बाहर निकाला जाता है और

दूसरे राज्य में जोड़ा गया, और उस अर्थ में कला। 3 (ख) और 3 (सी) को कुछ मामलों में सह-संबंधित कहा जा सकता है;

लेकिन कला करता है। 3 (ग) एक ऐसे मामले को संदर्भित करें जहां किसी राज्य के क्षेत्र के एक हिस्से को उस राज्य से बाहर ले जाया जाता है और नहीं

किसी अन्य राज्य में जोड़ा जाता है लेकिन किसी विदेशी राज्य को सौंप दिया जाता है? विद्वान महान्यायवादी तर्क देते हैं कि कला में उपयोग किए गए शब्द। 3 (ग) किसी विदेशी देश के पक्ष में राष्ट्रीय क्षेत्र के हस्तांतरण के मामले को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक हैं जो विचाराधीन राज्य के क्षेत्र को कम करने का कारण बनता है। हम इस तर्क से प्रभावित नहीं हैं। प्रथम दृष्टया यह सुझाव देना अनुचित प्रतीत होता है कि के निर्माता

संविधान के समर्पण के लिए प्रावधान करना चाहता था

कला के तहत राष्ट्रीय क्षेत्र। 3 (सी)। यदि विदेशी क्षेत्र को प्राप्त करने की शक्ति जो संप्रभुता की एक आवश्यक विशेषता है, द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं की जाती है संविधान में ऐसा कोई कारण नहीं है कि राष्ट्रीय क्षेत्र के एक हिस्से को सौंपने की शक्ति जो संप्रभुता की एक आवश्यक विशेषता भी है, प्रदान की जानी चाहिए थी।

संविधान के अनुसार। संप्रभुता के ये दोनों आवश्यक गुण संविधान के बाहर हैं और भारत द्वारा एक संप्रभु राज्य के रूप में इनका प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए, भले ही कला। 3 (ग) जितना व्यापक अंतर-दावा प्राप्त करता है, इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल होगा कि इसमें किसी विदेशी राज्य के पक्ष में राष्ट्रीय क्षेत्र के एक हिस्से के हस्तांतरण का मामला शामिल है। किसी भी राज्य के क्षेत्र का ह्रास, जिसे वह संदर्भित करता है, यह अभिधारणा करता है कि विचाराधीन राज्य से कम किया गया क्षेत्र भारत के क्षेत्र का हिस्सा होना चाहिए और बना रहना चाहिए; यह किसी अन्य राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकता है या कला द्वारा अधिकृत किसी अन्य तरीके से निपटा जा सकता है। 3 या संविधान के अन्य प्रासंगिक प्रावधान, लेकिन यह भारत के क्षेत्र का हिस्सा नहीं रहेगा। यह कला की भाषा पर अनावश्यक रूप से दबाव डालना होगा। 3 (ग) यह अभिनिर्धारित करना कि निहितार्थ से यह राष्ट्रीय क्षेत्र के किसी भाग के हस्तांतरण के मामलों के लिए प्रावधान करता है। इसलिए, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि राष्ट्रीय क्षेत्र को सौंपने की शक्ति को अनुच्छेद में नहीं पढ़ा जा सकता है। 3 ((ग) निहितार्थ द्वारा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1960]

292

एक और विचारणीय बात है

कला के निर्माण में सक्षम महत्व। 3 (सी)। जैसा कि हम पहले ही आर्ट का संकेत दे चुके हैं। 3 शब्दों में केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख नहीं करता है, और इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि कला। 3 (ग) उन्हें शामिल नहीं करता है; और इसलिए, यदि केंद्र शासित प्रदेशों के एक हिस्से को किसी विदेशी राज्य को सौंपना है

कला से संबंधित कानून। 3 इस तरह के हस्तांतरण के संबंध में सक्षम होगा यदि केंद्र शासित प्रदेशों के एक हिस्से के हस्तांतरण की सही स्थिति अनुच्छेद 368 से संबंधित कानून द्वारा अनिवार्य रूप से लागू की जानी चाहिए; और यह, हमारी राय में, उस अर्थ का दृढ़ता से समर्थन करता है जिसे हम कला पर रखने के लिए इच्छुक हैं। 3 ((ग) किसी विदेशी राज्य के पक्ष में किसी राज्य के क्षेत्र के हस्तांतरण के संबंध में भी। यह सुझाव देना अनुचित, अतार्किक और विसंगत होगा, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों के एक हिस्से के हस्तांतरण को कला से संबंधित कानून द्वारा लागू किया जाना चाहिए। 368 , राज्य क्षेत्रों के एक हिस्से के हस्तांतरण को अनुच्छेद के तहत कानून द्वारा लागू किया जा सकता है। 3. इसलिए हम विद्वान महान्यायवादी के इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि एक समझौता जिसमें एक विदेशी राज्य के पक्ष में भारत के क्षेत्र के एक हिस्से का हस्तांतरण शामिल है, संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत एक कानून पारित करके संसद द्वारा लागू किया जा सकता है। हम सोचते हैं कि यह सम्मेलन

सायन कला के एक निष्पक्ष और उचित निर्माण का अनुसरण करता है। 3 और इसकी वैधता को भारत के संघीय संविधान की विशेष विशेषताओं के रूप में वर्णित विद्वान अटॉर्नी-जनरल द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता है।

इस संबंध में विद्वान महान्यायवादी ने

और अधिनियम के प्रारंभ से असम राज्य के क्षेत्रों में अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्र की पट्टी शामिल नहीं होगी जो भूटान सरकार को सौंप दी जाएगी, और असम राज्य के बद्ध क्षेत्र निम्नलिखित माने जाएंगेः तदनुसार परिवर्तन किए गए हैं। धारा 3 में पहले के परिणामी संशोधन का प्रावधान है। असम के क्षेत्र से संबंधित संविधान की पहली अनुसूची के भाग ए में अनुच्छेद।

तर्क 3 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट है।

293

कि जब संसद भूटान सरकार के पक्ष में असम राज्य के एक हिस्से के क्षेत्र के हस्तांतरण पर विचार कर रही थी, तो उसने इस अधिनियम को अनुच्छेद के तहत पारित करने का इरादा किया था। 3 संविधान का। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार जो क्षेत्र दिया गया था, उसमें लगभग 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल था। देवनगिरी हिल ब्लॉक में क्षेत्र के मीलों की चरम उत्तरी सीमा पर देवनगिरी का एक हिस्सा होने के कारण

जी.

कामरूप जिला। क्षेत्र की यह पट्टी काफी हद तक थी

जंगलों से घिरा हुआ है और केवल बहुत कम भोटिया रहते हैं। विद्वान महान्यायवादी ने विधायी व्यवहार के रूप में इस एकल क़ानून पर भरोसा नहीं किया है। उन्होंने इसे केवल एक उदाहरण के रूप में उद्धृत किया है जहाँ पार्लिया

कला से संबंधित एक कानून बनाकर भूटान सरकार के पक्ष में असम क्षेत्र के एक हिस्से के हस्तांतरण को प्रभावी बना दिया है। 3 में से

संविधान। हमें नहीं लगता कि यह उदाहरण दायरे और प्रभाव को समझने में कोई सहायता कर सकता है। कला के प्रावधान। 3 .

इसलिए हमारा निष्कर्ष है कि यह नहीं होगा

संबंधित कानून बनाने के लिए संसद के लिए सक्षम

कला. 3 लागू करने के उद्देश्य से संविधान समझौते पर हस्ताक्षर करें। यह विद्वान द्वारा स्वीकार किया जाता है

महान्यायवादी ने कहा कि यह निष्कर्ष अनिवार्य रूप से होना चाहिए

इसका मतलब है कि सहमति को लागू करने के लिए आवश्यक कानून

कला के तहत पारित किया जाना चाहिए। 368 .

कला. 368 इस प्रकार पढ़ता हैः

कला. 368. इस संविधान का संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में इस उद्देश्य के लिए एक विधेयक पेश करके शुरू किया जा सकता है, और जब विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से पारित किया जाता है और

उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों का बहुमत,

राष्ट्रपति को उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है और विधेयक को ऐसी सहमति दिए जाने पर संविधान में निम्नलिखित के अनुसार संशोधन किया जाएगा - विधेयक की शर्तें:

बशर्ते कि यदि ऐसा संशोधन इसमें कोई परिवर्तन करना चाहता है

(क) अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 162

या अनुच्छेद 241, या

(ख) भाग 5 का अध्याय 4, भाग 6 का अध्याय 5,

या भाग XI का अध्याय I, या

((ग) सातवीं अनुसूची की किसी भी सूची में, या

((घ) संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, या

((ङ) इस अनुच्छेद के प्रावधान,

संशोधन को भी अनुमोदित करने की आवश्यकता होगी एक-आधे से कम नहीं के विधानमंडल

विधेयक के प्रावधान करने से पहले वे विधान मंडल इस तरह के संशोधन के लिए राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है

सहमति के लिए "।

हम पहले ही मान चुके हैं कि समझौते की राशि

भारत के क्षेत्र के एक हिस्से को पाकिस्तान के पक्ष में सौंपने के लिए; और इसलिए इसके कार्यान्वयन में स्वाभाविक रूप से कला की सामग्री में परिवर्तन और उसके परिणामस्वरूप संशोधन शामिल होगा। 1 और रील का यह संविधान की पहली अनुसूची का हिस्सा है, क्योंकि इस तरह के कार्यान्वयन से अनिवार्य रूप से भारत संघ का क्षेत्र कम हो जाएगा। इस तरह का संशोधन अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है। 368 . यह स्थिति विवाद में नहीं है और इसे हमारे सामने चुनौती नहीं दी गई है; इसलिए यह कला के तहत कार्य करने का अनुसरण करता है। 368 संसद बेरूबरी संघ संख्या 12 के एक हिस्से के साथ-साथ कुछ कूच-बिहार एन्क्लेव के हस्तांतरण को शामिल करने वाले प्रश्नगत समझौते को प्रभावी बनाने और लागू करने के लिए एक कानून बना सकती है, जो बदले में पाकिस्तान को दिए जाते हैं। संसद कर सकती है,

तथापि, यदि वह ऐसा चाहे, तो अनुच्छेद में संशोधन करते हुए एक कानून पारित करें। 3 संविधान की धारा, ताकि किसी विदेशी राज्य के पक्ष में भारत के क्षेत्र के हस्तांतरण के मामलों को शामिल किया जा सके। यदि ऐसा कोई कानून पारित हो जाता है तो संसद संशोधित अनुच्छेद के तहत कानून बनाने के लिए उपयुक्त हो सकती है। 3 विचाराधीन समझौते को लागू करना। दूसरी ओर, यदि आवश्यक कानून अनुच्छेद के तहत पारित किया जाता है। 368 केवल यही समझौते को लागू करने के लिए पर्याप्त होगा।

एक और का उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा।

इससे पहले कि हम संदर्भित प्रश्नों पर अपनी राय तैयार करें। हम पहले ही देख चुके हैं कि कला के प्रावधान के तहत। 3 संविधान में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां विधेयक में प्रस्ताव निहित है

किसी भी राज्य के क्षेत्र, सीमाओं या नाम को प्रभावित करता है, विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा 3 एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्टों को भेजा जाना है।

295

उस राज्य के विधान-मंडल को उस अवधि के भीतर उस पर अपने विचारों के लिए, जो उसमें विहित है। विद्वान वकील द्वारा हमारे समक्ष यह आग्रह किया गया है

सामान्य कि यदि यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि संसद को अनुच्छेद के तहत कार्य करना चाहिए। 368 और कला के तहत नहीं। 3 समझौते को लागू करने के लिए, यह प्रभावी रूप से पश्चिम बंगाल के विधानमंडल को विचाराधीन क्षेत्र के हस्तांतरण पर अपने विचार व्यक्त करने के अवसर से वंचित कर देगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सच है, लेकिन अगर यह उचित और उचित है।

निर्माण कला। 3 क्या यह आकस्मिक लागू नहीं होता है परिणाम से बचा नहीं जा सकता है। दूसरी ओर, यह स्पष्ट है कि यदि इम्प्लमेन के संबंध में कानून

समझौते को अनुच्छेद के तहत पारित किया जाना है। 368 उसे उक्त अनुच्छेद द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा; विधेयक को प्रत्येक सदन में सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित और मतदान करने वाले सदन के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाना चाहिए; अर्थात, इसे सदन के एक बड़े हिस्से की सहमति प्राप्त करनी चाहिए जिसका अर्थ आम तौर पर सदन के प्रमुख दलों की सहमति हो सकती है, और यह इस तरह के मामलों में अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा है।

इस संबंध में संयोग से यह इंगित किया जा सकता है

कि कला का संशोधन। 1 किसी विदेशी राज्य के पक्ष में भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद के परंतुक द्वारा निर्धारित सुरक्षा को आकर्षित नहीं करता है। 368 क्योंकि न तो कला। 1 न ही कला। 3 संविधान के निहित प्रावधानों की सूची में शामिल है परंतुक में उल्लिखित। यह पूछना या विचार करना हमारा काम नहीं है कि क्या उक्त दो अनुच्छेदों को परंतुक के तहत शामिल करना उचित नहीं होगा। यह संसद को विचार करने और निर्णय लेने का विषय है।

हम तदनुसार तीन प्रश्नों का उत्तर देंगे।

हमें निम्नानुसार संदर्भित किया गया हैः

प्र. 1. हां.

प्र. 2. (क) संसद का एक कानून जो कला से संबंधित हो। 3

संविधान अक्षम होगा;

(ख) संसद का एक कानून जो कला से संबंधित हो। 368

संविधान सक्षम और आवश्यक है;

(ग) संसद का एक कानून जो दोनों से संबंधित हो।

कला. 368 और कला। 3 यह केवल तभी आवश्यक होगा जब संसद पहले अनुच्छेद में संशोधन करने वाला कानून पारित करने का विकल्प चुनती है।

जैसा कि ऊपर बताया गया है; उस मामले में संसद को अनुच्छेद के तहत उन तर्ज पर एक कानून पारित करना पड़ सकता है। 368 और फिर संशोधित कला से संबंधित कानून के साथ इसका पालन करें। 3 समझौते को लागू करना।

प्र. 3. प्रश्न 2 के उत्तर (ए), (बी) और (सी) के समान।

संदर्भ ने तदनुसार उत्तर दिया।